



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254835  
CG-DL-E-21062024-254835

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 2024/ज्येष्ठ 25, 1946

No. 160]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 2024/JYAISHTHA 25, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 जून 2024

अंतिम निष्कर्ष

मामला सं. सीवीडी/एसएसआर-09/2023

विषय: चीन जन. गण. और वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के आयात से संबंधित सब्सिडी रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जाँच।

## 1. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/23/2023-DGTR.—1. नामित प्राधिकरण द्वारा 9 अगस्त, 2018 को चीन जन. गण. और वियतनाम (जिसे इसके बाद "विषय देश" भी कहा गया है) से वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबंधित वस्तुएं" भी कहा गया है) के आयात की एक सब्सिडी-रोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद पदनामित प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन सरकार और वियतनामी सरकार द्वारा संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों

को प्रदान की गई राजसहायता प्रतिमान्य प्रकृति की थी और संबंधित वस्तुओं का संबंधित देशों से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर निर्यात किया गया था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची थी। नतीजतन, प्राधिकरण ने 31 जुलाई 2019 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/22/2018-डीजीएडी के तहत संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

2. संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा दायर एक आवेदन के अनुसरण में, नामित प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन की आवश्यकता की जांच करने के लिए 11 फरवरी 2021 की अधिसूचना के माध्यम से प्रतिकारी शुल्क की सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू की। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि निर्यातक द्वारा अनुरोध किए गए उत्पाद बहिष्करण को अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/45/2020-डीजीटीआर दिनांक 8 फरवरी 2022 के तहत वारंट नहीं किया गया था।
3. स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली, और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात (इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक संघ" के रूप में संदर्भित) ने व्यापार नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के तहत प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। भारत में संबंधित वस्तुओं के अपने सदस्यों और उत्पादकों की ओर से किए गए इस आवेदन में चीन जन. गण. और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइपों के आयात से संबंधित सब्सिडी विरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया था। आवेदकों के चालीस (40) सदस्यों (इसके बाद "आवेदक घरेलू उत्पादक" या "घरेलू उद्योग" के रूप में संदर्भित) ने व्यापार नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार डेटा प्रस्तुत किया।
4. अधिनियम की धारा 9(6) के अनुसार, लगाए गए प्रतिकारी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किए जाते हैं, लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगे। प्राधिकरण से यह समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या प्रतिशुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अलावा, नियमों के नियम 24(3) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

*"अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चित प्रतिकारी शुल्क इसके लागू होने की तारीख से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा। अभिहित प्राधिकारी उस अवधि से पूर्व या तो अपनी पहल पर अथवा उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उक्त प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार ऐसे अधिरोपण की अवधि को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना।*

5. उपर्युक्त के अनुसार और घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर प्राधिकरण को इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या राजसहायता रोधी शुल्कों की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
6. आवेदकों ने 31 जुलाई 2023 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें पहले लगाए गए प्रतिकारी शुल्कों की सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया और चीन जन. गण. और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइप के आयात के खिलाफ सब्सिडी रोधी शुल्क जारी रखने की मांग की गई। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि वियतनाम से सब्सिडाइज्ड विषय वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और

उपायों की समाप्ति के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद पर राजसहायता जारी रहने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

7. वियतनाम से आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन और चीन जन. गण. और वियतनाम से आयात के कारण सब्सिडी और क्षति की संभावना को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया और अधिनियम की धारा 9 (6) के अनुसार, नियमों के नियम 24 के साथ पढ़ा गया, प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 07/23/2023- डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2023 के माध्यम से सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू की, ताकि चीन जन. गण. और वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यात की जाने वाली संबंधित वस्तुओं के संबंध में सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर सब्सिडी-रोधी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी जारी रहने या फिर से होने और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

## 8. प्रक्रिया

9. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 17 सितंबर, 2019 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/22/2018-डीजीटीआर के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
10. वर्तमान जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- I. उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें वियतनाम से आयात के कारण क्षति और राजसहायता जारी रहने की संभावना तथा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की आशंका व्यक्त की गई थी।
  - II. प्राधिकरण ने नियम 6(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन जनगण और वियतनाम के दूतावासों को अधिसूचित किया।
  - III. प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 07/23/2023 दिनांक 30 सितंबर 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, असाधारण, संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा शुरू की।
  - IV. उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रपिठ की गई थी ताकि उन्हें नियमों के नियम 7(2) के अनुसार विषय की जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया जा सके।
  - V. प्राधिकरण ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों और अन्य इच्छुक पार्टियों को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की, जिन्होंने नियम के नियम 7 (3) के अनुसार लिखित रूप में अनुरोध किया। आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छुक पार्टियों को भी प्रदान की गई थी, जहां भी अनुरोध किया गया था।
  - VI. प्राधिकरण ने सनसेट रिव्यू जांच शुरू करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति विषय देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को अग्रपिठ की और उन्हें दीक्षा अधिसूचना या विस्तारित समय सीमा में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने का अवसर

प्रदान किया, और नियमों के नियम 7(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करें। प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पार्टियों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली भी जारी की।

VII. प्राधिकरण ने चीन सरकार, जनगण समिति और वियतनाम सरकार को एक प्रश्नावली भेजी थी जिसमें विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना मांगी गई थी जहां संबंधित देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिमान्य लाभ प्रदान किए गए हों। तथापि, चीन सरकार के जनगण अथवा वियतनाम सरकार द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया था।

VIII. प्राधिकरण ने निर्यातक प्रश्नावली संबंधित देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अग्ररपित की:

- क. एमेटल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ख. फोशान मेटलवेल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ग. फोशान नानहाई झोउयिंग हार्डवेयर एसीसी, चीन पीआर
- घ. ग्वांगडोंग फॉरेन ट्रेड इंप. एंड एक्सप. कंपनी, चीन पीआर
- ङ. ग्वांगडोंग सुमविन न्यू मटेरियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- च. गुआंगफेंग स्टील कॉर्पोरेशन, चीन पीआर
- छ. हैमेन सेंडा डेकोरेशन मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ज. जियांगसू न्यू किउजिंग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- झ. जियांग सिटी बाओवेई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ञ. लो मेटल्स लिमिटेड, चीन पीआर
- ट. मिनिमेटल्स स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ठ. ओकाया (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ड. पोहांग (झांगजियागांग) स्टेनलेस स्टील प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ढ. शेडोंग हुआये स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी, चीन पीआर
- ण. शंघाई हाइस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- त. शांक्सी ताइगांग स्टेनलेस स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- थ. लिंगशान होल्डिंग ग्रुप शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- द. वूशी सिटी स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- ध. वूशी जॉयरे इंटरनेशनल कॉर्प, चीन पीआर
- न. ज़ियामेन गोल्डन हुआनन इंप. एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- प. यंग मेटल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- फ. युयाओ जिंगडा स्टेनलेस स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- ब. झांगजियागांग पोहांग स्टेनलेस स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- भ. झेजियांग हुआशुन मेटल मैटेरियल्स कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर
- म. झेंशी ग्रुप ईस्टर्न स्पेशल स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन पीआर

- य. जिया एन हंग येन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 कक. जिया एनह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम  
 खख. हा एनह स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 गग. इनाॅक्स होआ बिन्ह, जेएससी, वियतनाम  
 घघ. मिन्ह हू लीन जेएससी, वियतनाम  
 डड. नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 चच. ओस दाई दुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम  
 छछ. सोन्हा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वियतनाम  
 जज. स्टील 568 कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 झझ. टैप इंटरनेशनल, जेएससी, वियतनाम, वियतनाम  
 जज. तुआन डाट मेटल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 टट. विनायनाॅक्स, वियतनाम  
 ठठ. विनलॉन्ग स्टेनलेस स्टील (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- IX. विषय देशों की सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के व्यौरों के साथ संबंधित देशों के दूतावासों को भेजी गई थी।
- X. विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली का जवाब दायर किया:
- क. सोन्हा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वियतनाम  
 ख. स्टील 568 कं, लिमिटेड, वियतनाम  
 ग. टीवीएल स्टील प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम  
 घ. जिया अन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम  
 ड. ओएसएस दाईदुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी  
 च. नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड
- XI. प्राधिकरण ने अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबंधित वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अग्ररूपित की और आवश्यक सूचना मांगी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर नहीं दिया है।
- XII. प्राधिकरण ने संबंधित देशों के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आथक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आथक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल आवेदकों द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है।
- XIII. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, साथ ही सभी पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें।
- XIV. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

- XV. आवेदकों ने कहा कि उनके पास डीजीसीआई एंड एस के लेनदेन-वार डेटा तक पहुंच नहीं है और इसलिए, भारत में आयात के बारे में जानकारी बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार प्रदान की गई थी। प्राधिकरण द्वारा प्रणाली महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात और जांच की अवधि का लेनदेन-वार ब्यौरा प्रदान करें, जो प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था।
- XVI. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन आवेदक संघों द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से व्यापार नोटिस 09/2021 के तहत किया गया था। आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था, जिसमें 18 संस्थाओं के डेटा थे। प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश भर में संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राधिकरण ने यह पता लगाने की मांग की कि क्या 18 कंपनियों के आंकड़ों में देखे गए रुझान व्यापक उद्योग के प्रतिनिधि थे। इसके लिए, प्राधिकरण ने संघों से संबद्ध कंपनियों से अतिरिक्त डेटा का अनुरोध किया। इस विस्तारित डेटा सेट के विश्लेषण से पता चला है कि सभी प्रमुख आर्थिक पैरामीटर प्रारंभिक डेटा में पहचाने गए रुझानों के साथ संरेखित हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के भीतर बड़ी संख्या में उत्पादकों की उपस्थिति के कारण संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना, और बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में शामिल जटिलता के कारण, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में नमूने का विकल्प चुना।
- XVII. प्राधिकरण ने नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों से आवश्यक सीमा तक और सूचना मांगी। नमूना घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- XVIII. प्राधिकरण ने अन्य इच्छुक पार्टियों से आवश्यक सीमा तक और सूचना मांगी। अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आयोजित किया गया था। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में इच्छुक पार्टियों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- XIX. गैर-हानिकारक मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार भारत में संबंधित वस्तुओं को बनाने और बेचने के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत और लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- XX. नियमों के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों को 14 मई 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- XXI. इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, उठाए गए तर्क और जांच के दौरान विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जिस हद तक साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं, इस प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।
- XXII. प्राधिकरण ने जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया जो संभव सीमा तक इस प्रकटन विवरण का आधार बनता है और प्रासंगिक, व्यवहार्य तथा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

- XXIII. गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराएं
- XXIV. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे इच्छुक पक्षों को गैर-सहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटीकरण विवरण को दर्ज किया।
- XXV. \*\*\* इस अंतिम निष्कर्ष में गोपनीय आधार पर एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।
- XXVI. विषयगत अन्वेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 US\$ = ₹ 81.06 है।

### 11. विचाराधीन और पसंद किए जा रहे लेख का दायरा

#### ग1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

12. इच्छुक पक्षों में से एक ने प्राधिकरण से चल रही जांच में मूल जांच में विचार किए गए पीसीएन को अपनाने का अनुरोध किया, जो नीचे दिए गए हैं

क. 200 श्रृंखला

ख. 300 श्रृंखला

ग. 400 श्रृंखला

#### ग2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

13. विचाराधीन अथवा इसी प्रकार के लेख के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।
- क. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब है। विषय वस्तुएं 200, 300 और 400 श्रृंखलाओं से बनी होती हैं। तदनुसार, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर पीसीएन का प्रस्ताव किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं विचाराधीन देश से आयात किए जा रहे उत्पाद-दर-वस्तु के समान होती हैं।

#### ग3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप है। वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहता है।
15. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोड 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि संबंधित वस्तुओं का आयात एचएस कोड 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304

90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90. सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

16. इच्छुक पाटयों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण ने उचित तुलना के लिए पीसीएन पद्धति को अपनाया उपयुक्त समझा। प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया।

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर (स्टील का ग्रेड)	कोड
1.	200 श्रृंखला	2एस
2.	300 श्रृंखला	3एस
3.	400 श्रृंखला	4एस

17. वर्तमान जांच में अंतिम रूप दिए गए पीसीएन मूल जांच के समान हैं। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है यानी "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब"।
18. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और संबंधित देशों से आयातित वस्तुएं भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों, उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण, विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपरोक्त दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबंधित देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की वस्तु की तरह हैं।

### घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

#### घ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

19. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।
- क. वर्तमान जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन का 25% हिस्सा नहीं है। प्राधिकरण लगातार सूर्यास्त समीक्षा में नियम 6 (3) (ए) के संदर्भ में खड़े होने का परीक्षण लागू करता है।
- ख. घरेलू उद्योग का गठन करने वाले किसी भी घरेलू उत्पादक ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार अनुलग्नक-1 दायर नहीं किया है। तदनुसार, वर्तमान जांच को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
- ग. प्राधिकरण घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे निर्माता वे हो सकते हैं जिनकी बिक्री लागत अधिक है और जिन्हें आंतरिक कारणों से नुकसान हो रहा है। व्यापार सूचना 09/2021 निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय रूप से मान्य तकनीकों के आधार पर नमूना चयन निर्धारित करती है।

#### घ2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

20. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:



- क. आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात द्वारा व्यापार नोटिस 09/2021 के तहत दायर किया गया है।
- ख. भारतीय उद्योग 100 से अधिक उत्पादकों से बना है। आवेदक संघों के 40 सदस्यों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डेटा दायर किया है।
- ग. अन्य इच्छुक पक्षों के तर्क के विपरीत, आवेदन दाखिल करने के समय, आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सा था।
- घ. आवेदन दाखिल करते समय 18 कंपनियों ने डेटा दाखिल किया, दाखिल करने के बाद 22 और कंपनियों ने प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की, जिससे घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन का 50% तक बढ़ गई।
- ङ. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पादों का आयात संबंधित देशों से नहीं किया है और वे किसी निर्यातकर्ता/आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- च. कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण घरेलू मांग के लगभग 70% की पूत करने वाले अपस्ट्रीम उत्पाद के सबसे बड़े भारतीय उत्पादकों में से एक, जेएसएसएल द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए आपूर्ति की गई कच्ची सामग्री के आधार पर किया गया है।
- छ. पांच नमूना उत्पादकों के साथ-साथ सात अन्य उत्पादकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पूर्ण लागत डेटा दायर किया है। प्राधिकरण अपने सूक्ष्म विश्लेषण के लिए किसी भी स्वयंसेवी निर्माता को जोड़ने का विकल्प चुन सकता है।
- ज. अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्क के विपरीत, वर्तमान जांच प्रतिकारी नियमों के नियम 24 के तहत शुरू की गई एक सूर्यास्त समीक्षा है। संशोधित नियमों के अनुसार, नियम 6 समीक्षा पर लागू नहीं होता है और स्थिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### घ3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

21. वर्तमान समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन व्यापार सूचना 09/2021 के तहत भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के दो पंजीकृत संघों द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उद्योग की ओर से स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स मैनुफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात द्वारा आवेदन दायर किया गया है।
22. प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच में एमएसएमई सेगमेंट में निर्माता शामिल हैं। विषय वस्तुओं का निर्माण करने वाला भारतीय उद्योग प्रकृति में खंडित है और भारत में विषय वस्तुओं के 100 से अधिक उत्पादक हैं।
23. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि भारत में कई उत्पादक हैं, इसलिए उनके पास भारत में संबंधित वस्तुओं के कुल उत्पादन तक पहुंच नहीं है। कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड ("जेएसएसएल") द्वारा दायर जानकारी पर भरोसा किया है। रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार, जेएसएसएल भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, अर्थात्, स्टेनलेस स्टील काइला। जेएसएसएल की भारत में कच्चे माल की मांग के बाजार में \*\*\*% हिस्सा है। जांच की अवधि के दौरान

जेएसएसएल ने भारत में \*\*\* मीट्रिक टन कच्चे माल की आपूर्ति की है। कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण ने 105 के सायन मानदण्डों पर विचार किया है।

विवरण		मात्रा (एमटी)
जिंदल द्वारा आपूर्ति की गई कुंडल	ए	***
दूसरों द्वारा आपूर्ति की गई कुंडल	बी = ए/70%*30%	***
कुल कुंडल की आपूर्ति	सी = ए + बी	***
अनुमानित भारतीय उत्पादन*	डी = सी/1.05	***
श्रेणी	एमटी	250000-350000

\*खपत मानदंड 1.05

24. प्रतिकारी शुल्क नियमों के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के निर्माण में लगे हुए हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडाइज्ड वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों, या अन्य देशों की वस्तु की तरह हों या स्वयं उसके आयातक हों, 'घरेलू उद्योग' शब्द की व्याख्या बाकी उत्पादकों के संदर्भ में की जा सकती है।

25. अन्य इच्छुक पक्षों की प्रस्तुतियों के बारे में कि नियम 6 वर्तमान जांच पर लागू होता है, प्राधिकरण नोट करता है कि चूंकि वर्तमान समीक्षा नियम 24 के तहत की जा रही है, इसलिए नियम 6 लागू नहीं होता है। नियम 24 निम्नानुसार है:

(1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिकारी शुल्क तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक और यथा आवश्यक हो, सब्सिडीज, जिससे क्षति हो रही है, का प्रतिकार करने के लिए।

(2) नामित प्राधिकारी प्रतिकारी शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करेगा, जहां अपनी पहल पर या किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा अनुरोध पर वारंट किया गया है जो इस तरह की समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करता है, और निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाने के बाद से और इस तरह की समीक्षा पर उचित अवधि बीत चुकी है, जब यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त प्रतिकारी शुल्क हटा दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है और इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अभिहित प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेगा।

(3) अधिनियम के अधीन लगाया गया कोई निश्चित प्रतिकारी शुल्क उसके अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी होगा। अभिहित प्राधिकारी उस अवधि से पूर्व या तो अपनी पहल पर अथवा उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उक्त प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार ऐसे अधिरोपण की अवधि बढ़ाने के लिए सिफारिश करना।

(4) उपनियम (1) के अधीन आरंभ की गई कोई पुनरावलोकन ऐसी समीक्षा आरंभ होने की तारीख से बारह मास से अनधिक की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

[बशर्ते कि नियम 19 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी समीक्षा समीक्षाधीन प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले पूरा किया गया।]

[(5) उपनियम (4) के अधीन रहते हुए, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंध समीक्षा के मामले में उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू होंगे।

26. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि कुछ उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत डेटा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे डेटा विरूपण हो सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि जब उत्पादकों की संख्या बहुत बड़ी है और संख्या में 100 से अधिक है और ये उत्पादक ज्यादातर एमएसएमई और खंडित हैं। घरेलू उद्योग ने 18 कंपनियों की क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है जिसकी विधिवत जांच की गई। इसके अलावा, अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से 22 और संस्थाओं के क्षति पैरामीटर से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया है। आगे की जांच करने पर, प्राधिकरण ने नोट किया कि 18 संस्थाओं के मामले में पाई गई क्षति की प्रवृत्ति ज्यादातर 22 अतिरिक्त संस्थाओं के समान है और प्रवृत्ति 40 संस्थाओं के लिए भी समान है।

## ड. गोपनीयता

### ड1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

27. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

- क. आवेदक संघों ने व्यापार नोटिस 09/2021 की आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज दाखिल नहीं किए हैं। यदि ऐसे दस्तावेज दायर किए गए हैं, तो मौखिक सुनवाई के अवसर के साथ अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रदान किया जा सकता है।
- ख. आवेदकों ने बिक्री मूल्य के रूप में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जांच का समर्थन या विरोध करने वाले संघों के सदस्यों की सूची को गोपनीय दावा किया गया है। व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुसार, घरेलू उद्योग को कई उत्पादकों के मामले में वास्तविक जानकारी का खुलासा करना होगा। व्यापार सूचना में निर्धारित सिद्धांत प्रतिकारीजांच पर भी लागू होते हैं। गोपनीयता स्वतः नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसकी पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है जैसा कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था।
- ग. ईसी में अपीलीय निकाय द्वारा आयोजित गोपनीयता का दावा करने के लिए आवेदकों को अच्छा कारण दिखाना चाहिए - चीन से कुछ लौह या इस्पात फास्टनरों। प्राधिकरण घरेलू उद्योग को स्पष्ट फ्लोट ग्लास पर जांच में दिए गए निर्देश के अनुसार याचिका का उचित गैर-गोपनीय संस्करण दायर करने का निर्देश दे सकता है। आवेदकों द्वारा आवेदन का उचित एनसीवी दायर किए जाने के बाद नए सिरे से सुनवाई की जा सकती है।

### ड2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

28. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं

- क. टीवीएल स्टील कंस्ट्रक्शन एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोना एसएसपी वियतनाम एंड स्टील 568 कंपनी ने अपनी स्वामित्व संरचना, शेयरधारकों, संबद्ध कंपनियों, संबद्ध संस्थाओं द्वारा निष्पादित गतिविधियों की प्रकृति, चाहे उसने संबद्ध/सरकारी संस्था से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए इनपुट खरीदे हों, के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. टीवीएल स्टील कंस्ट्रक्शन और जेएससी ने दावा किया है कि उसने कच्चे माल के लिए किसी भी आयात शुल्क छूट के लिए आवेदन नहीं किया है या लाभ नहीं उठाया है, प्रदान की गई जानकारी को गोपनीय दावा किया गया है। परिशिष्ट-1 को गोपनीय बताया गया है।
- ग. अन्य इच्छुक पार्टियों के विवाद के विपरीत, संघों के दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें व्यावसायिक मालिकाना जानकारी होती है जिसे अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
- घ. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीयता पर दायर की गई टिप्पणियां विलम्बित प्रकृति की हैं क्योंकि ये याचिका के गैर-गोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के बाद दायर की गई हैं।
- ङ. जबकि आवेदकों ने मात्रा मापदंडों के संबंध में समग्र वास्तविक जानकारी का खुलासा किया है, मूल्य पैरामीटर गोपनीय व्यवसाय संवेदनशील सूचना है जिसके प्रकटीकरण से प्रतियोगियों को अनुचित लाभ मिलेगा।

### ड3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, प्रतिकारी शुल्क नियमों के नियम 8 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) और नियम 19 के उप-नियम (3), नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई किसी भी अन्य जानकारी में निहित किसी भी बात के बावजूद, नामित प्राधिकारी द्वारा अपनी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकेगा कि संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आपूतकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटीकरण को किसी सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्राधिकृत करने के लिए या तो अनिच्छुक है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकेगा।

30. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया और इच्छुक पक्षों को ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को साझा करने का निर्देश दिया।
31. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने संघों के दस्तावेजों को साझा नहीं किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि संघों के दस्तावेजों में बैठकों के मिनट, एसोसिएशन के उप-नियमों के साथ-साथ एसोसिएशन के ज्ञापन भी शामिल हैं जिनमें व्यावसायिक स्वामित्व की जानकारी होती है और अन्य इच्छुक पार्टियों को इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।
32. बिक्री मूल्य पर गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि बिक्री मूल्य में बिक्री की मात्रा और मूल्य शामिल हैं। ये व्यावसायिक स्वामित्व वाली जानकारी हैं और बाजार में अन्य निर्माता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसकी गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से अन्य इच्छुक पार्टियों को अनुचित लाभ मिलेगा। इसलिए, प्राधिकरण ने ऐसी जानकारी पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है।

### च. विविध मुद्दे

#### च1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

33. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई विविध प्रस्तुतियां नहीं की गई हैं।

#### च2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

34. घरेलू उद्योग ने कोई विविध प्रस्तुतियां नहीं दी हैं।

### क. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

#### क.1 अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

35. अन्य इच्छुक पार्टियों ने सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
- I. चूंकि उत्पादक/निर्यातक ने जांच में पूरा सहयोग किया है, इसलिए दायर की गई प्रतिक्रिया के अनुसार माजन निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे व्यक्तिगत शुल्क प्रदान किया जा सकता है।
  - II. निर्यातक ने मूल जांच में भाग नहीं लिया क्योंकि इसने 2019-20 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 2021-22 में भारत को निर्यात किया। भागीदारी का यह पहला अवसर है।
  - III. एक नया निर्यातक सनसेट समीक्षा में व्यक्तिगत शुल्क के लिए पात्र है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्राधिकरण ने दीक्षा अधिसूचना के माध्यम से नए निर्यातकों सहित सभी इच्छुक पार्टियों से सूचना का अनुरोध किया है। वीएसएफ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एनएफवाई, एल्युमिनियम फॉइल, एनबीआर, एनटीसीएफ और जूट के आयात जैसी कई जांचों में, प्राधिकरण ने सूर्यास्त समीक्षा में पहली बार उत्पादकों को व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित किए हैं। इंडियन ग्रेफाइट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम डीए में सीईएसटीएटी ने माना कि प्राधिकरण सूर्यास्त समीक्षा में नए निर्यातकों के लिए पाटन रोधी शुल्क तय कर सकता है।

- IV. प्राधिकरण द्वारा की गई एक सूर्यास्त समीक्षा मूल जांच के समान है जैसा कि रॉबिन रिसोर्सेज बनाम नामित प्राधिकारी में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया था। चूंकि वर्तमान जांच में प्राधिकरण सब्सिडियों के निर्धारण के लिए संगत सभी पैरामीटरों की जांच कर रहा है, इसलिए नए निर्यातक को व्यक्तिगत दर पर शुल्क प्रदान न करने का कोई औचित्य नहीं है।
- V. निर्यातक उत्पादकों / निर्यातकों की सरकार द्वारा दी गई किसी भी सब्सिडी का प्रतिकार करने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है, न कि किसी तीसरे देश की सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर।
- VI. विषयगत वस्तुओं के अधिकांश भारतीय उत्पादक भी चीन जनगण से कच्चे माल का आयात करते हैं। लाभ के माध्यम से पारित होने के किसी भी दावे का मतलब होगा कि भारतीय उत्पादकों को चीन जन. गण. से आयातित कच्चे माल पर सब्सिडी भी मिल रही है।
- VII. सब्सिडी के पासश्रू का दावा मूल जांच में किया गया था और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

## क.2 घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी और सब्सिडी माजन मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

- I. संबंधित देशों की सरकारों ने विभिन्न सब्सिडी के रूप में इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।
- II. कुछ स्कीमों के अंतर्गत लाभ अनावर्ती हैं और इनकी विषय वस्तुओं के औसत उपयोगी जीवन काल की जांच की जानी चाहिए।
- III. केवल सरकार ही इस बात से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती है कि उक्त योजना प्रतिदेय है या नहीं। एक निर्यातक केवल इस बात की जानकारी प्रदान कर सकता है कि कोई लाभ प्राप्त हुआ था या नहीं।
- IV. चीन से हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों, जो संबंधित वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री है, के आयातों से संबंधित सब्सिडी-रोधी जांच में प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चीन सरकार विभिन्न प्रतिवैधीय सब्सिडियां प्रदान करती है।
- V. चीन सरकार ने लोहा और इस्पात उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं जिसके कारण अत्यधिक क्षमता और अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। यह वियतनाम में विदेशी उत्पादकों पर भी फैल गया है, जिन्होंने भारत को सब्सिडी वाले सामान निर्यात किए हैं।
- VI. किसी भी चीन सरकार अथवा चीन के उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- VII. किसी सूचना के अभाव में प्राधिकरण उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच कर सकता है।
- VIII. चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों की निरंतरता का विरोध नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान जांच में कथित नई योजनाओं की जांच नहीं की जानी चाहिए और चीन में सब्सिडी की परीक्षा केवल मौजूदा शुल्क की निरंतरता तक ही सीमित हो सकती है।
- IX. होल्लिंग कंपनी और जिया अन्ह हंग येन की बहन कंपनी ने वर्तमान जांच में प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है।
- X. प्राधिकरण संबद्ध संस्थाओं के बारे में जानकारी मांग सकता है।
- XI. प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध कंपनियों के भाग न लेने की स्थिति में प्राप्त सब्सिडियों का पूर्ण ब्यौरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

- XII. निर्माता ने प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया है और पूरी प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है, जिससे इसकी प्रतिक्रिया अस्वीकृति के लिए उपयुक्त है।
- XIII. निर्यात किए गए उत्पादों के लिए निविष्टियों पर आयात शुल्क में दी गई छूट तब तक प्रतिदेय नहीं है जब तक कि छूट केवल निर्यातित उत्पादों के उत्पादन तक ही दी जाती है।
- XIV. यदि ऐसी प्रणाली मौजूद नहीं है या प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जाती है, तो इससे छूट की पूरी राशि का प्रतिवाद होगा।
- XV. प्राधिकरण को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर राजसहायता मार्जिन की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।
- XVI. अन्य न्यायालयों में, जहां निर्यातक देश की सरकार सहयोग नहीं करती है, जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करते हैं और योजनाओं की प्रतिवादीयता निर्धारित करते हैं।
- XVII. कुछ निर्यातक/उत्पादक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II का उत्तर देने में असफल रहे हैं।
- XVIII. मूल जांच में शून्य प्रतिशत मार्जिन वाले उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में इस जांच में कथित नई सब्सिडी की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- XIX. निर्यातकों ने यह नहीं दिखाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी या सबूत सटीक नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने इसे शुरू करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
- XX. इस्पात उत्पादों के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी, जिसे प्राधिकरण द्वारा चीन के हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के मामले में अपने निष्कर्षों में प्रतिप्रापण्य पाया गया है, विदेशी उत्पादकों, यहां तक कि वियतनाम में भी, ऐसे उत्पादकों को भारत सहित अन्य देशों को गैर-प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

### क.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

37. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन ने वस्तु विषय पर विषय देश में प्रतिवाधा योग्य सब्सिडियों के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया। प्राधिकरण नोट करता है कि चीन और वियतनाम की सरकारों को लिखित संचार और परामर्श के माध्यम से, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के अस्तित्व, संचालन और प्रशासन, डब्ल्यूटीओ एएससीएम और भारतीय नियमों की तुलना में इसकी प्रतिशीलता, और इन योजनाओं के तहत संबंधित देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकरण नोट करता है कि चीन सरकार ने न तो प्रश्नावली का जवाब दायर किया है, न ही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं से संबंधित कोई जानकारी प्रदान की है। इस प्रकार, चीन की सरकार वर्तमान जांच में प्राधिकरण के साथ सहयोग करने में विफल रही है। चूंकि चीन की सरकार ने आवश्यक सहयोग नहीं बढ़ाया है, इसलिए प्राधिकरण वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के उद्देश्य से सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के साथ आगे बढ़ने के लिए विवश है। वियतनाम सरकार द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर को रिकार्ड में ले लिया गया है और प्राधिकरण द्वारा उसकी जांच की गई है।
38. वर्तमान जांच प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर शुरू की गई थी। आरंभ होने के बाद, विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली का प्रत्युत्तर निर्धारित रूप और तरीके से दाखिल करने की सलाह दी गई थी और उन्हें ऐसी सब्सिडियों की मौजूदगी और मात्रा का उचित निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, डिग्री और प्रभाव पर सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था।

यदि कोई हो। तथापि, चीन से संबंधित वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किए हैं जबकि वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर दायर किए हैं

- i. स्टील 568 कंपनी लिमिटेड
- ii. सोना एसएसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड
- iii. टीवीएल स्टील प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
- iv. जिया हीरो येन कं, लिमिटेड
- v. नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड
- vi. ओएसएस दैयांग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

39. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातक सरकारों के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत प्रतिदेय सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें छह व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुदान, कर और वैट प्रोत्साहन, अधिमान्य ऋण और ऋण / वित्तपोषण, निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल का प्रावधान, और इक्विटी इन्फ्यूजन।

### क.3.1 चीन जन. गण. के संबंध में सब्सिडी

40. चीन के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित योजनाओं के खिलाफ जांच शुरू की है:

i. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर पानी का प्रावधान
- ख. सरकार द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किए गए हॉट रोलड स्टील (एचआरएस) के अंतर्गत हॉट रोलड स्टील (एचआरएस) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ग. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोल्ड-रोल्ड का प्रावधान (एलटीएआर)
- घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर स्टील स्क्रेप के लिए सरकारी प्रावधान
- ङ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किए गए भूमि उपयोग अधिकार
- च. एसओई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
- छ. एलटीएआर के लिए निकेल/निकल पिग आयरन का प्रावधान
- ज. एलटीएआर के लिए फेरोक्रोम/क्रोमियम का प्रावधान
- झ. एलटीएआर के लिए कोकिंग कोल का प्रावधान
- ञ. एलटीएआर में लौह अयस्क
- ट. एलटीएआर पर बिजली
- ठ. कोक पर निर्यात प्रतिबंध



ड. एलटीएआर के लिए भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान - कुछ औद्योगिक और एसईजेड में भूमि उपयोग अधिकार

ii. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं

क. आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और वैट छूट

ख. उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां।

ग. मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें

घ. छोटे लाभ पर काम करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता

ङ. टियांजिन पोर्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यम आयकर दर में कमी

च. विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित टैक्स क्रेडिट

छ. व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चे माल) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें

ज. शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

झ. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश और विदेशी उद्यमों वाले उद्यमों के लिए आयकर में कटौती

ञ. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां

ट. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति

ठ. विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई मुनाफे के पुनः निवेश के लिए आयकर वापसी

ड. कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालित करने के लिए निर्धारित उत्पादक एफआईई के लिए कम कर की दर

ढ. उन्नत प्रौद्योगिकी एफ.आई.ई. के लिए आयकर में कमी

ण. एफआईई और विदेशी उद्यमों और कुछ घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनके पास चीन में प्रतिष्ठान या स्थान हैं और घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों की खरीद के उत्पादन या व्यवसाय संचालन में लगे हुए हैं

त. एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां

थ. घरेलू स्तर पर एफआईई खरीदने के लिए वैट रिफंड - उत्पादित उपकरण

द. प्रौद्योगिकी या ज्ञान-गहन एफ.आई.ई. के लिए कर कटौती

ध. उच्च तकनीक उपलब्धि व्यावसायीकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगर कर वापसी

न. उत्पादक एफ.आई.ई. के लिए स्थानीय आयकर और कमी कार्यक्रम

प. स्थानीय आयकर छूट और/या गुआंगडोंग और हैनान द्वीप में एसईजेड में कमी

फ. इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक पार्क

ब. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट

- भ. तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- iii. अधिमान्य ऋण और ऋण के रूप में पहचानी गई योजनाएं
- क. जीओसी द्वारा क्रेडिट गारंटी
- ख. अधिमान्य ऋण (पॉलिसी ऋण सहित)
- ग. चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमान्य निर्यात वित्तपोषण
- घ. एसओई के लिए अधिमान्य ऋण
- ङ. ऋण ब्याज का भुगतान करने के लिए भत्ता
- iv. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचानी गई योजनाएं
- क. निर्यात विक्रेता का क्रेडिट
- ख. निर्यात खरीदार का क्रेडिट
- ग. निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी
- घ. राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण
- v. इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में पहचानी गई योजनाएं
- क. इक्विटी स्वैप के लिए ऋण
- ख. इक्विटी इन्फ्यूजन
- ग. अवैतनिक लाभांश
- घ. ऋण माफी
- ङ. विलय या पुनर्गठन के दौर से गुजर रहे एसओई के लिए विलेख कर छूट
- vi. अनुदान के रूप में पहचानी गई योजनाएं
- क. प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम /
- ख. ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष कोष
- ग. जिआंगसु प्रांत द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
- घ. बाओशन स्टील को अनुदान
- ङ. एंटीडंपिंग जांच के लिए अनुदान
- च. सुपरस्टार एंटरप्राइज ग्रांट
- छ. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
- ज. निर्यात सहायता अनुदान
- झ. शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुदान

- ज. गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए धन
- ट. राजकोषीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रांतीय कोष के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
- ठ. अनुदान - विदेशी व्यापार के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि
- ड. घरेलू और विदेशी मेले में भाग लेने के लिए झोंगशम उद्यमों के लिए भत्ते के फंड प्रबंधन के अंतरिम उपाय
- ढ. निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
- ण. छोटे और मध्यम आकार के उद्यम सहायता कोष
- त. प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि
- थ. ट्रेजरी बॉन्ड, ऋण या अनुदान
- द. प्रांतीय सरकार - उपकरण अनुदान
- ध. फुयांग शहर और हांगजो शहर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
- i. करों में आरएमबी 10 मिलियन से अधिक का भुगतान करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
  - ii. उप-अनुबंध सेवाओं के निर्यात कार्यक्रम के तहत अनुदान
  - iii. उत्कृष्ट नए उत्पाद/प्रौद्योगिकी पुरस्कार के तहत अनुदान
  - iv. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग शहर सरकार से निवेश अनुदान
  - v. उद्यमों ऑपरेटिंग प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए अनुदान
  - vi. निर्यात ऋण बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान
  - vii. प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) हांगजो प्रान्त और फुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से अनुदान
- न. हेबै प्रांत द्वारा प्रदान किए गए अनुदान
- i. हेबै प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
  - ii. शीज़ियाज़ूआंग सिटी एक्सपोर्ट अवार्ड की सरकार
- प. शेडोंग प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
- i. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए शेडोंग प्रांत का विशेष कोष
  - ii. प्रमुख ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगीकरण के लिए शेडोंग प्रांत का पुरस्कार कोष
  - iii. शेडोंग प्रांत के पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधि
  - iv. प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शेडोंग प्रांत का निर्माण कोष
- फ. टियांजिन बिनहाई न्यू एरिया और टियांजिन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

ब. उत्सर्जन में कमी के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को शंघाई नगर सब्सिडी

vii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचानी गई योजनाएं

क. सरकार द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर माल की खरीद

41. न्यायिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्राधिकारी को उन कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जांच करने से परहेज करने की अनुमति देता है जिन्हें मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था। प्राधिकारी को यह जांच करनी है कि क्या मूल जांच के दौरान निर्धारित प्रतिसंतुलन योग्य योजनाएं जारी हैं और क्या उक्त योजनाओं के तहत निरंतर लाभ प्राप्त होने का सबूत है। वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा जांच है, और जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या चीनी उत्पादकों को प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी से लाभ मिलना जारी है। हालांकि, चीन सरकार और चीन जन.गण. के निर्यातक सहयोग करने और कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी देने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए प्रस्तुतियां दी हैं कि चीन में उत्पादक और निर्यातक ऐसी प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी का लाभ उठाना जारी रखते हैं। इस प्रकार, चीन सरकार या उसके उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य के अभाव को देखते हुए कि क्या ऐसी योजनाओं को वापस लिया गया है या नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियां, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी योजनाएं चीन में मौजूद हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान करती हैं।
42. सूर्यास्त समीक्षा जांच में, प्राथमिक ध्यान सब्सिडी की निरंतरता या पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति की संभावना निर्धारित करना है। मूल जांच के विपरीत, जहां कम शुल्क नियम के सिद्धांत को लागू करने के लिए वर्तमान सब्सिडी या क्षति मार्जिन को स्थापित करना और मात्रा निर्धारित करना आवश्यक है और तदनुसार कर्तव्यों की दर निर्धारित करें, वर्तमान विश्लेषण इन कारकों की संभावना और पहले से मौजूद कर्तव्यों की निरंतरता पर केंद्रित है। नतीजतन, वर्तमान परिस्थितियों में जहां प्राधिकरण के समक्ष कोई नया या विपरीत तथ्य पेश नहीं किया गया है, प्राधिकरण इन योजनाओं के संबंध में न्यायिक अर्थव्यवस्था का प्रयोग करता है जो पहले संबोधित की गई थीं और मूल जांच में प्रतिरूप मानी गई थीं। इस प्रकार, मौजूदा सब्सिडी माजन को बनाए रखा जाना है और प्राधिकरण इस प्रकार सनसेट समीक्षा जांच के विषय के लिए सब्सिडी योजनाओं की विस्तृत जांच के अभ्यास को दोहराने से खुद को प्रतिबंधित करता है।

#### वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए नए कार्यक्रम

43. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि एक और काउंटरवेलेबल स्कीम 'एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सब्सिडी' है जो निर्यातकों/उत्पादकों को लाभ प्रदान करती है, जिससे उन्हें कम कीमतों पर बेचने की अनुमति मिलती है। उत्पादकों/निर्यातकों अथवा जीओसी द्वारा इस योजना के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने भी इस कार्यक्रम के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है ताकि संबंधित देश से उत्पादकों/निर्यातकों को प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा निर्धारित की जा सके। पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकरण कथित रूप से नए राजसहायता कार्यक्रम की समतुल्यता की जांच करना उचित नहीं समझता है। तदनुसार, वर्तमान जांच के उद्देश्य से नए कार्यक्रम की जांच नहीं की गई है।
44. उत्पादकों/निर्यातकों और जीओसी से कोई उत्तर न मिलने की स्थिति में प्राधिकरण को मूल जांच में प्राधिकरण के निष्कर्षों के साथ-साथ जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/साक्ष्य सहित रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए, प्राधिकरण मूल जांच में अपने निष्कर्षों के आधार पर उपर्युक्त कार्यक्रमों को प्रतिवाद के रूप में जारी रखता है। इस प्रकार, प्राधिकरण ने मूल जांच में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन के बराबर सब्सिडी निर्धारित की है।

क्र.सं	योजना का नाम	सीवीडी मार्जिन	श्रेणी
1.	अनुदान	***	0-10
2.	कर और वैट प्रोत्साहन	***	0-10
3.	अधिमान्य ऋण	***	0-10
4.	एलटीएआर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रावधान (ए + बी + सी)	***	30-40
क.	एलटीएआर पर बिजली	***	0-10
ख.	एलटीएआर में प्रदान किए गए भूमि उपयोग अधिकार	***	0-10
ग.	एलटीएआर में कच्चा माल	***	20-30
	कुल सब्सिडी मार्जिन	***	30-40

### क.3.3 वियतनाम के संबंध में सब्सिडी

#### योजनाओं को पहले मूल जांच में प्रतिवाद के रूप में पाया गया

45. वियतनाम के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित योजनाओं के खिलाफ जांच शुरू की है:

*i. कर प्रोत्साहन और छूट के रूप में पहचानी गई योजनाएं*

- क. कच्चे माल के लिए आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति
- ख. अचल संपत्ति बनाने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क छूट
- ग. उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट
- घ. उद्यम आयकर पर कानून के अध्याय III के तहत उद्यम आयकर छूट

*ii. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचानी गई योजनाएं*

- क. निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण
- ख. निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

*iii. निवेश प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं*

- क. निर्यातकों को अधिमान्य ऋण
- ख. लघु-मध्यम उद्यमों को सहायता
- ग. निवेश ऋण की ब्याज दर
- घ. छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना पर निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश समर्थन पर।

*iv. बैंकों से लाभ के रूप में पहचानी गई योजनाएं*

- क. वियतनाम विकास बैंक से निर्यात क्रेडिट
- ख. वियतनाम बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण गतिविधि
- ग. वियतनाम बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी
- घ. निर्यात समर्थन ऋण

*v. विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदान की जा रही योजनाओं की पहचान की गई*

- क. प्रोत्साहित उद्योगों या औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए भूमि वरीयता
- vi. *यूटिलिटियों के उपयोग पर प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं*
- क. पानी के किराए पर छूट या कमी
- ख. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि किराए से छूट या कटौती
46. मूल जांच में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रतिशोधी पाया।
- I. कर प्रोत्साहन और छूट के रूप में पहचानी गई योजनाएं**
1. कार्यक्रम संख्या 1: डिक्री 24 के अध्याय V के तहत आयकर प्राथमिकताएं (उद्यम आयकर पर कानून का कार्यान्वयन)
  2. कार्यक्रम संख्या 2: कच्चे माल के लिए आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति
  3. कार्यक्रम संख्या 3: उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट
- II. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचानी गई योजनाएं**
4. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यातकों को अधिमान्य ऋण
  5. कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम
  6. कार्यक्रम No 7: निर्यात क्रेडिट वियतनाम विकास बैंक फार्म
  7. कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात समर्थन क्रेडिट
- III. निवेश प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं**
8. कार्यक्रम संख्या 9: निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण
  9. कार्यक्रम संख्या 10: निवेश क्रेडिट ऋण की ब्याज दर
  10. कार्यक्रम संख्या 11: विदेशी निवेशकों पर निवेश सहायता पर जिन्होंने निवेश किया था छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना
- IV. बैंकों से लाभ के रूप में पहचानी गई योजनाएं**
11. कार्यक्रम संख्या 13: वियतनाम बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी
- V. विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होने के लिए चिन्हित योजनाएं**
12. कार्यक्रम संख्या 14: प्रोत्साहित उद्योगों में उद्यमों के लिए भूमि वरीयताएँ या डिक्री 142 के तहत औद्योगिक क्षेत्र
- VI. उपयोगिताओं के उपयोग पर प्रोत्साहन के लिए पहचानी गई योजनाएं**
13. कार्यक्रम संख्या 15: पर्याप्त से कम भूमि के लिए सरकार का प्रावधान पारिश्रमिक और छूट या भूमि और पानी के किराए से कटौती

**विषय जांच में प्रतिरूप पाई गई योजनाएं**

47. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों ने मुख्य रूप से सब्सिडी जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना और परिणामी क्षति लगने का आरोप लगाया है। इसलिए, विषय जांच में प्राधिकरण ने मुख्य रूप से सब्सिडी की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना और वर्तमान कर्तव्यों की समाप्ति की स्थिति में परिणामी क्षति के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया है।

48. प्राधिकारी नोट करता है कि प्रारंभिक जांच में, प्रतिसंतुलन योग्य मानी गई योजनाएं भी भाग लेने वाले निर्यातकों/उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाली पाई गई थीं। चल रही सनसेट समीक्षा जांच में, भाग लेने वाले निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया कि उन्हें कथित योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि, यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने प्रतिसंतुलन योजनाओं से लाभ लेना बंद कर दिया है, प्राधिकरण को प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, वियतनाम सरकार (जीओवी) ने अपने प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से दावा किया है कि कथित कार्यक्रमों को बंद नहीं किया गया है और साथ ही उक्त कार्यक्रमों में कोई प्रत्याशित परिवर्तन भी नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान परिस्थितियों में जहां प्राधिकरण के समक्ष कोई नया या विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्राधिकरण इन योजनाओं के संबंध में न्यायिक मितव्ययिता का प्रयोग करता है, जिन्हें पहले मूल जांच में संबोधित किया गया था और प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था। इस प्रकार, मौजूदा सब्सिडी मार्जिन को बनाए रखा जाना है और प्राधिकरण इस प्रकार विषयगत सनसेट समीक्षा जांच के लिए सब्सिडी योजनाओं की विस्तृत जांच के अभ्यास को दोहराने से खुद को प्रतिबंधित करता है।
49. प्राधिकरण ने पाया कि नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में गंभीर रूप से कमी थी और प्राधिकरण द्वारा विनिदष्ट प्रारूप का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह जांच के तहत कार्यक्रमों के बारे में कोई प्रासंगिक जानकारी, दस्तावेज या सबूत प्रदान करने में विफल रहा। नतीजतन, प्राधिकरण को निर्यातक/उत्पादक के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसा कि सीवीडी नियम, 1995 के नियम 7 (8) में उल्लिखित है।
50. निर्यातक/उत्पादक ओएसएस दाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने बताया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया। इस दावे को प्राधिकरण द्वारा डीजी सिस्टम डेटा का उपयोग करके सत्यापित किया गया है। इसके अलावा, यह जांचने के लिए कि क्या ओएसएस अभी भी वर्तमान जांच के पीओआई के दौरान मूल जांच में प्रतिशोधित सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठा रहा था, जांच दल ने ओएसएस से अनुरोध किया कि वह अपनी प्रतिक्रिया को सत्यापित करने के लिए रिमोट डेस्क सत्यापन में भाग ले। हालांकि, OSS इस अनुरोध का प्रतिसाद देने में विफल रहा। ओएसएस की ओर से जानबूझकर की गई इस चूक ने प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने की प्राधिकरण की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(8) के अंतर्गत यथा निर्धारित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ओएसएस के राजसहायता मार्जिन की गणना की है।
51. जिया अनह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने दावा किया था कि उसने पीओआई के दौरान भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था। इस दावे की जांच टीम ने डीजी सिस्टम डेटा के जरिए पुष्टि की। जिया अनह ने निर्यातक प्रश्नावली का पूरा जवाब दाखिल किया है। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या जिया अनह ने मूल जांच में प्रतिशोधित किसी भी योजना के तहत वर्तमान जांच के पीओआई में लाभ उठाया था, जांच दल ने अपनी प्रतिक्रिया के सत्यापन के लिए रिमोट डेस्क सत्यापन बैठक में उपर्युक्त निर्यातक/उत्पादक में भाग लेने का अनुरोध किया। रिमोट डेस्क सत्यापन के दौरान, जिया अनह ने दावा किया कि उसने किसी भी योजना के तहत कोई लाभ नहीं लिया है। जांच टीम ने जिया अनह से सब्सिडी योजनाओं के बारे में कई सवाल पूछे। कार्यक्रम सं. 3 और 14 के अंतर्गत सब्सिडी के लाभ की जांच करते समय, जांच दल ने गिया आन्ह को हंग येन प्रांत की पीपुल्स कमेटी द्वारा जारी निवेश नीति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। इस प्रमाणपत्र के अनुसार, गिया आन्ह वियतनाम में उच्च श्रेणी के स्टेनलेस स्टील उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहनों की हकदार हैं। इसके अलावा, प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट किया गया है कि यह पात्रता 13 नवंबर, 2052 तक प्रभावी रहेगी। गिया आन्ह को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था कि उसने अपने वित्तीय विवरणों के आधार पर योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभ नहीं उठाया है। हालांकि, निर्यातक कंपनी के प्रतिनिधि अपने इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रहे कि कंपनी ने लाभ उठाना जारी नहीं रखा। चूंकि जांच दल प्रतिसंतुलित योजनाओं के अंतर्गत

दिए गए लाभ की मात्रा में वृद्धि के संबंध में कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया, इसलिए प्राधिकरण ने मूल जांच में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन को जारी रखा है।

### वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए नए कार्यक्रम

52. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि लाभ प्रदान करने वाले तीन काउंटरवेलेबल कार्यक्रम हैं जिससे वियतनाम में उत्पादकों को कम कीमत पर बेचने की अनुमति मिलती है। ऐसे नए कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है:

- क. निर्यात किए गए माल के आयात पर छूट
- ख. उद्यम आयकर पर कानून के अध्याय III के तहत उद्यम आयकर छूट
- ग. लघु-मध्यम उद्यमों को सहायता

51. प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने ऊपर वर्णित नए कार्यक्रमों के अस्तित्व का आरोप लगाया है, आरोपों को प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण नए कथित कार्यक्रमों की प्रतिवाद की जांच करने की स्थिति में नहीं है।

प. सं.	कार्यक्रम का नाम	सोनहा एसएसपी वियतनाम	स्टील 568 कंपनी लिमिटेड	अवशिष्ट
पी.1	डिक्री 24 के अध्याय V के अंतर्गत आयकर वरीयताएँ (उद्यम आयकर पर कानून का कार्यान्वयन)	शून्य	शून्य	0-5%
पी. 3	उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट			
पी.2	कच्चे के लिए प्रतिपूर्ति पर आयात शुल्क छूट भौतिक	शून्य	शून्य	शून्य
पी.5	निर्यातकों को अधिमाम्य ऋण	शून्य	शून्य	0-5%
पी.6	निर्यात संवर्धन कार्यक्रम	शून्य	शून्य	0-5%
पी.7	वियतनाम विकास बैंक के रूप में निर्यात क्रेडिट	शून्य	शून्य	0-5%
पी.8	निर्यात समर्थन ऋण	शून्य	शून्य	0-5%
पी.9	निवेशकों के लिए अधिमाम्य ऋण	शून्य	शून्य	0-5%
पी.10	निवेश ऋण की ब्याज दर	शून्य	शून्य	0-5%
पी.11	छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना पर निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश समर्थन पर।	शून्य	शून्य	0-5%
पी.13	विएतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी	शून्य	शून्य	0-5%
पी.14	प्रोत्साहित में उद्यमों के लिए भूमि वरीयताएँ डिक्री 142 के तहत उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र	(0-5%)	(0-5%)	0-5%
पी.15	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि और पानी के किराए से छूट या			



	कटौती			
अन्य	अचल संपत्ति बनाने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क में छूट	शून्य	शून्य	0-5%
	कुल सब्सिडी मार्जिन %	***	***	***
	कुल सब्सिडी मार्जिन (रेंज %)	डी-मिनिमिस	डी-मिनिमिस	10-20%

छ. क्षति और कारण लिंक का आकलन और सब्सिडी और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

### छ1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

52. क्षति, कारण लिंक और सब्सिडी और क्षति की संभावना के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति हुई है और न ही क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री मूल्य, पीवीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि हुई है।
- ख. प्रतिवादियों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति अथवा क्षति की पुनरावृत्ति अथवा जारी रहने की संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों का आयात मूल्य बढ़ गया है और जांच अवधि के दौरान यह उच्चतम था। चूंकि प्रतिवादियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए सब्सिडी रोधी शुल्क लागू न होने की स्थिति में भी मूल्य निर्धारण व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होगा।
- ग. वियतनाम से प्रमुख आयात शुल्क से छूट प्राप्त स्रोतों से होते हैं, घरेलू उद्योग के आथक मानदंडों जिनमें घरेलू बिक्री, बिक्री मूल्य और लाभ शामिल हैं, में सुधार हुआ है। चूंकि ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए लागू राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग को जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, तो वह केवल चीन से आयातों के कारण है। यह इस तथ्य के कारण है कि चीनी आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को 30-40% तक कम कर रहे हैं।
- ङ. यह आशंका है कि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य अहानिकर मूल्य से अधिक है और इस कारण आवेदकों ने आवेदन में अहानिकर मूल्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि गैर-हानिकारक मूल्य निवल बिक्री मूल्य से अधिक है, तो प्राधिकरण की सतत प्रक्रिया के अनुसार जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- च. आवेदकों ने पुनरावृत्ति अथवा क्षति के जारी रहने की संभावना का कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है।
- छ. वियतनाम से आयात मूल्य में वृद्धि हुई है और यह अन्य देशों से आयात मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि निर्यातक सीमा शुल्क के अभाव में भी उचित कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं।

### A छ2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

53. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, कारणात्मक लिंक और राजसहायता एवं क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं

- क. वर्तमान जांच में क्षति के संचयी मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चीन से आयात नगण्य है और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है। वियतनाम से आयात और विशेष रूप से उत्पादकों द्वारा राजसहायता रोधी शुल्क न लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।
- ख. विषय देशों की सरकारों ने विषय देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा है।
- ग. वियतनाम से आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि आयातकों की ओर से है जो सब्सिडी रोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है।
- घ. वियतनाम में छूट वाले उत्पादकों से आयात मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है।
- ङ. सब्सिडी-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन उत्पादकों से आयात में गिरावट आई है जो भारत में उचित मूल्यों पर बिक्री करने में विदेशी उत्पादकों की असमर्थता को दर्शाता है।
- च. वियतनाम में छूट प्राप्त उत्पादकों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग की संभाव्यता और मौजूदा बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है।
- छ. भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जांच की मूल अवधि से पूर्व भारतीय उद्योग द्वारा धारित बाजार शेयर से काफी कम है।
- ज. घरेलू उद्योग में भारत में पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए, आयात पर निर्भरता पूरी तरह से अनावश्यक है।
- झ. वियतनाम से आयात औसत आधार पर घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। पीसीएन-वार आधार पर मूल्य कम करना अधिक है।
- ञ. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे कम थी।
- ट. वियतनाम से आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी।
- ठ. वियतनाम से कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को मार्जिन पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर आय में गिरावट आई है।
- ड. सब्सिडी रोधी शुल्क के अभाव में आयात बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से चीन से कच्चे माल के आयात पर भारत में प्रतिकारीशुल्क और पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कच्चे माल को चीन से वियतनाम को स्थानांतरित किया जा रहा है।
- ढ. प्राधिकरण ने हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स में यह निर्णय दिया है कि चीन में कच्चे माल के विनिर्माताओं को महत्वपूर्ण राजसहायता प्रदान की जा रही है। ऐसी सब्सिडी का लाभ वियतनाम में उत्पादकों को दिया गया है।
- ण. चीन में स्टेनलेस स्टील की काफी और अधिक क्षमताएं हैं जैसा कि प्राधिकरण ने चीन से हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर अंतिम निष्कर्षों में कहा है। चूंकि विषय वस्तुएं न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ स्टेनलेस स्टील के डाउनस्ट्रीम उत्पाद हैं, इसलिए सब्सिडी रोधी शुल्क के अभाव में ऐसी निर्यात योग्य क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।

- त. सोहना एसएसपी और इस्पात ने उत्पादन मात्रा और क्षमता उपयोग में वृद्धि की सूचना दी है। सोहना एसएसपी ने भी क्षमता में वृद्धि की सूचना दी है।
- थ. जबकि चीन जनगण में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता है, चीन में इस्पात की मांग में गिरावट आई है। चीनी उत्पादकों को अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है।
- द. तुर्किये, यूरोशियन इकॉनॉमिक यूनियन, यूएसए और ब्राजील जैसे अनेक देशों ने विषयगत वस्तुओं के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं।
- ध. आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आने और राजसहायता रोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है।

### छ3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

54. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इच्छुक पार्टियों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण के तहत इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।
55. अनुबंध-1 के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली, 1995 के नियम 13 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में राजसहायता प्राप्त आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं के मूल्यों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन कारकों की जांच शामिल है जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं।
56. प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और संगत कानूनी प्रावधानों पर विचार किया है। नीचे दी गई जांच वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग और इच्छुक पार्टियों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में दिए गए प्रस्तुतीकरण से संबंधित है।
57. प्राधिकरण ने राजसहायता और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पहले विषय देशों से आयातों के कारण विभिन्न क्षति मानदंडों की जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन या खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। मूल्यों पर राजसहायता प्राप्त आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में राजसहायता प्राप्त वस्तुओं के मूल्य की तुलना में राजसहायता प्राप्त आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा। भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडाइज्ड आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, सब्सिडी का परिमाण और माजन आदि पर नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुसार विचार किया गया है।
58. नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 4 में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ सब्सिडी-रोधी जांच की जा रही है, प्राधिकरण ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन कर सकता है यदि वह यह निर्धारित करता है कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित सब्सिडी का मार्जिन एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है, और

ख. आयातित उत्पादों और इसी प्रकार के घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

59. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि संचयी विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण नोट करता है कि चीन से आयात में गिरावट आई है और नगण्य है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार, प्राधिकरण ने वियतनाम से आयात के कारण हुई क्षति का आकलन किया।

### छ.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

60. प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	117	124
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	107	91
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	80	111	110
चीन से आयात	एमटी	36,584	408	616	129
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	1	2	0
अन्य आयात	एमटी	31,387	26,532	15,637	14,408
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	85	50	46
मांग		***	***	***	***
प्रवृत्ति	एमटी	100	91	96	90

61. यह देखा गया है कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में संबंधित वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, लेकिन इसके बाद 2021-22 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में फिर से गिरावट आई है। हालांकि, जांच अवधि के दौरान मांग काफी हद तक स्थिर रही है।

### छ.3.2 सब्सिडी वाले आयात का मात्रा प्रभाव

62. जहां तक राजसहायता प्राप्त आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकरण को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में राजसहायता प्राप्त आयातों में या तो निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष पर्याप्त वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।

संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात की मात्रा और क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान सस्मिडी वाले आयात का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310
चीन से आयात	एमटी	36,584	408	616	129
अन्य आयात	एमटी	31,387	26,532	15,637	14,408
कुल	एमटी	1,09,983	60,414	62,880	60,847
वियतनाम से आयात के संबंध में					
घरेलू उत्पादन	%	10-20	10-20	10-20	10-20
खपत	%	10-20	0-10	10-20	10-20

63. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति की जांच अवधि के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-2021 में वियतनाम से आयात की मात्रा में गिरावट आई है। हालांकि, 2020-2021 के बाद आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उत्पादन की तुलना में वियतनाम से आयात \*\*\*% से बढ़कर \*\*\*% हो गया है।
- ग. घरेलू खपत के संबंध में वियतनाम से आयात -\*\*\*% से बढ़कर \*\*\*% हो गया है।

### छ.3.3. रियायती आयातों का मूल्य प्रभाव

64. मूल्यों पर राजसहायता प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में इस प्रकार के उत्पादों के मूल्य की तुलना में कथित आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होता। आयातों के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच मूल्य कम करने, मूल्य कम करने और मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

#### क. कीमत कम करना

65. मूल्य कम कटौती का निर्धारण करने के लिए, व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के अवतरित मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, सभी छूटों और करों के निवल के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के मूल्य फैक्टरी स्तर पर निर्धारित किए गए थे।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	200 श्रृंखला	300 श्रृंखला
1	वियतनाम से आयात की लैंडिड कीमत	₹/एमटी	1,51,493	2,50,993
2	निवल विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***
3	मूल्य में कटौती	₹/एमटी	(***)	***
4	मूल्य में कटौती	%	(***)	***
5	मूल्य में कटौती	श्रेणी	(0-10)	0-10

यह देखा गया है कि हालांकि 200 श्रृंखलाओं के मामले में नकारात्मक मूल्य अंडरकटिंग हुई है, हालांकि, 300 श्रृंखला के मामले में \*\*\*% से लेकर सकारात्मक मूल्य अंडरकटिंग है।

#### क. मूल्य दमन/अवसाद

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव से मूल्यों में काफी कमी आती है अथवा मूल्य वृद्धि, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, को रोका जा सके, प्राधिकरण ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और मूल्यों में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	130	137
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	138	141
वियतनाम से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,56,842	1,71,120	2,02,932	2,43,168
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	129	155
चीन से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,08,347	1,33,597	2,39,300	1,83,228
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	123	221	169

68. प्राधिकरण नोट करता है कि, आधार वर्ष के दौरान, घरेलू उद्योग ने आयात से कुछ मूल्य दबाव का अनुभव किया, जैसा कि बिक्री मूल्य बिक्री की लागत से नीचे गिरने से स्पष्ट है। तथापि, क्षति की जांच अवधि के आधार वर्ष के बाद घरेलू उद्योग संबंधित वस्तुओं को बिक्री लागत से अधिक मूल्य पर बेचने में समर्थ रहा है जो घरेलू मूल्यों पर आयातों के परिणामस्वरूप मूल्य दबाव की अनुपस्थिति को दर्शाता है - चाहे यह दमन हो या मंदी।

69. तथापि, पीसीएन-वार तुलना के आधार पर प्राधिकरण नोट करता है कि 33 श्रृंखलाओं के लिए वियतनाम का अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वियतनाम से कम कीमत वाले आयात के कारण मार्जिन पर समझौता करने के लिए मजबूर किया गया है।

विवरण	इकाई	200 एस	300 एस
घरेलू उद्योग बिक्री मूल्य	₹/एमटी	***	***
श्रेणी	₹/एमटी	15,0,000-2,00,000	2,50,000-3,00,000
वियतनाम से आने वाली कीमत	₹/एमटी	1,51,493	2,50,993
चीन जन. गण.से आने वाली कीमत	₹/एमटी	1,01,052	2,32,182

70. कुछ इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को चीन से आयात के कारण नुकसान हुआ है क्योंकि चीन से आयात की उतराई कीमत वियतनाम की तुलना में कम है। प्राधिकरण नोट करता है कि चीन से आयात की उतराई कीमत वियतनाम से उतराई की कीमत से कम है, चीन से आयात की मात्रा नगण्य है। इतनी कम मात्रा को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

### छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

71. नियमों में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर आयातित विषय की परिणामी क्षति की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर राजसहायता प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंटरी, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

#### क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

72. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया था

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	109	131
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	119	130
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
श्रेणी	%	50-60	60-70	60-70	50-60
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	117	124

73. प्राधिकरण का मानना है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, उद्योग अपने इष्टतम स्तर पर काम करने या अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

#### ख. बाज़ार हिस्सेदारी

74. राजसहायता प्राप्त आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नानुसार जांच की गई है -

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	20-30	30-40	30-40	30-40
अन्य भारतीय निर्माता	%	40-50	40-50	40-50	40-50
वियतनाम से आयात	%	10-20	0-10	10-20	10-20
चीन जन. गण. से आयात	%	0-10	0-10	0-10	0-10
अन्य आयात	%	0-10	0-10	0-10	0-10

75. प्राधिकरण नोट करता है कि सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण राहत मिली है, जिससे वह जांच की अवधि के आधार वर्ष में अपनी बाजार हिस्सेदारी को \*\*\*% से बढ़ाकर जांच की अवधि में \*\*\*% करने में सक्षम हुआ है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि वियतनाम से आयात की प्रवृत्ति ने ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र का अनुभव किया है, जो आधार वर्ष में \*\*\*% से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान \*\*\*% हो गया है।

76. इसके अलावा, आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग द्वारा धारित बाजार हिस्सा जांच की मूल अवधि से पूर्व भारतीय उद्योग द्वारा धारित बाजार शेयर से काफी कम है। प्राधिकरण नोट करता है कि मूल जांच की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग द्वारा आयोजित सबसे कम बाजार हिस्सेदारी \*\*\*% थी जबकि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान भारतीय उद्योग द्वारा आयोजित उच्चतम बाजार हिस्सेदारी \*\*\*% थी। इस प्रकार, भारतीय उद्योग पहले की तुलना में बाजार हिस्सेदारी कम रखता है।

### ग. सूची

77. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	130	141	166

78. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में वृद्धि हुई है।

### घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी

79. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और वापसी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	130	137
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	138	141
लाभ / (हानि)	₹/एमटी	(***)	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	686	2,267	976
लाभ / (हानि)	₹ लाख	(***)	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	761	2,652	1,234
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	448	1,129	609
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	0-10	10-20	20-30	10-20



## 80. प्राधिकरण नोट करता है कि:

- i. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2021-2022 तक बढ़ गई, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें \*\*\*% की गिरावट आई है।
- ii. नियोजित पूंजी पर रिटर्न ने भी वही प्रवृत्ति दिखाई जो वर्ष 2021-2022 तक बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में \*\*\*% की गिरावट आई है।
- iii. घरेलू उद्योग ने कहा है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर वियतनाम से आयात के कारण उसे माजन पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

## ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

81. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारी	संख्या.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	116	137
प्रतिदिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	119	130
प्रतिदिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/ संख्या.	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	100	106	103	95

82. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। क्षति के कारण प्रति दिन उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, हालांकि, प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2020-2021 से घटने लगी और जांच की अवधि में और गिरावट का अनुभव किया है।

## च. वृद्धि

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	%	-	***	***	***
उत्पादन	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	%	-	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	-	(***)	***	(***)
नकद लाभ	%	-	***	***	(***)
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	-	***	***	(***)

83. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षमता ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो आधार वर्ष में \*\*\* की तुलना में जांच की अवधि में \*\*\*तक पहुंच गया है। हालांकि, घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष के \*\*\*से घटकर जांच की अवधि में \*\*\*रह गया है। घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री में भी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जो आधार वर्ष में \*\*\* से गिरकर जांच की अवधि के दौरान \*\*\* हो गई। इसके अलावा, क्षति की जांच अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित करने के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ और पूंजी पर वापसी दोनों नकारात्मक हो गए।

**छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

84. प्राधिकरण नोट करता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में कम हो गई है और नियोजित पूंजी पर लाभ में गिरावट दर्ज की गई है।

**ज. सब्सिडी मार्जिन का परिमाण**

85. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन वर्तमान जांच में सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

**ज. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना**

86. चूंकि, वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा जांच है, यह तथ्य कि क्या घरेलू उद्योग को वर्तमान में नुकसान नहीं हो रहा है, इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है कि कर्तव्यों को जारी रखा जाएगा या नहीं। सनसेट समीक्षा जांच में, प्राधिकरण को यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या किसी उपाय के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जो मूल जांच में किए गए निर्धारण के विपरीत है।

87. प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी जारी रहने या क्षति लगने की संभावना है या नहीं। प्राधिकरण ने राजसहायता अथवा क्षति के जारी रहने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

88. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने राजसहायता जारी रखने की संभावना और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को प्रभावित करने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की परीक्षा इस प्रकार है।

**ज1. प्रतिकारी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद निरंतर सब्सिडी**

89. प्राधिकरण नोट करता है कि लागू कर्तव्यों के बावजूद विषय देशों से संबंधित वस्तुओं की निरंतर सब्सिडी है। शुल्कों के अस्तित्व के दौरान निरंतर सब्सिडी सब्सिडी की निरंतरता की संभावना को इंगित करती है।

90. जबकि राजसहायता-रोधी शुल्क लागू होने के कारण चीन से आयातों की मात्रा नगण्य थी, दोनों देशों से 300 श्रृंखलाओं के आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम हैं।

विवरण	इकाई	200 एस	300 एस
घरेलू उद्योग बिक्री मूल्य	₹/एमटी	***	***
प्रवृत्ति	₹/एमटी	1,50,000- 2,00,000	2,50,000- 3,00,000
वियतनाम से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,51,493	2,50,993
चीन से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,01,052	2,32,182

91. प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-सब्सिडी शुल्क की समाप्ति के मामले में, सभी स्रोतों से आयात बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, ऐसे आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम मूल्य पर होने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

**ज2. चीन जनगण और उत्पादकों से आयात में कमी सब्सिडी रोधी शुल्क के अध्यक्षीन**

92. प्राधिकरण नोट करता है कि सब्सिडी रोधी शुल्क के अध्यक्षीन स्रोतों से हानि अवधि के दौरान विषय आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात	एमटी	36,584	408	616	129
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310
छूट प्राप्त उत्पादकों से आयात	एमटी	25,098	31,602	43,671	42,992
अन्य उत्पादकों से आयात	एमटी	16,915	1,872	2,955	3,318

93. प्राधिकरण नोट करता है कि सब्सिडी विरोधी शुल्क के अधीन उत्पादकों से आयात में गिरावट आई है। सब्सिडी-रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयातों में राजसहायता-रोधी शुल्क से छूट प्राप्त स्रोतों से आयात की प्रवृत्ति के अनुरूप होने की संभावना है। इस प्रकार, ऐसे आयातों से भारत में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है।

**ज3. चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमता**

94. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. में स्टेनलेस स्टील की महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमताएं हैं। प्राधिकरण नोट करता है, कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, चीन जन. गण. में स्टेनलेस स्टील की मांग में गिरावट आई है। चूंकि ये विषय वस्तुएं न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ स्टेनलेस स्टील के डाउनस्ट्रीम उत्पाद हैं, इसलिए चीन के उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग भारत को संबंधित वस्तुओं के निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।

**ज4. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय**

95. आवेदकों ने दावा किया है कि इन देशों के उत्पादक अर्जेटीना, यूरेशियन आर्थिक संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करते हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि विषय देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू होने के कारण राजसहायता रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में उत्पादकों के भारतीय बाजार में स्थानांतरित होने की संभावना है। इसके अलावा, चूंकि चीन जनगण में अतिरिक्त क्षमताएं हैं, अतः राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा भारत को विषयगत वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है।

दिनांक	उपाय लागू करने वाले देश	लगाए गए उपाय का प्रकार
10-07-2021	तुर्की	वियतनाम से आयात पर पाटन रोधी शुल्क
14-03-2021	यूरेशियन आर्थिक संघ	चीन से आयात पर पाटन रोधी शुल्क
03-12-2019	संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन और वियतनाम से आयात पर पाटन रोधी शुल्क
06-03-2019	संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन से आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क
13-06-2018	ब्राज़ील	वियतनाम से आयात पर पाटन रोधी शुल्क

**ज5. भारत में आयात बिक्री मूल्य से कम पर आ रहा है**

96. आवेदकों ने दावा किया है कि आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम कीमतों पर देश में आ रहा है।

विवरण	इकाई	200 एस	एस 300
घरेलू उद्योग बिक्री मूल्य	₹/एमटी	***	***
प्रवृत्ति	₹/एमटी	1,50,000-2,00,000	2,50,000-3,00,000
वियतनाम से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,51,493	2,50,993
चीन से उतरा हुआ मूल्य	₹/एमटी	1,01,052	2,32,182

97. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि के दौरान विषय आयात की उतराई कीमत नमूना उत्पादकों के बिक्री मूल्य से कम थी।

98. लागू राजसहायता रोधी शुल्क और वियतनाम में शुल्क के अध्यक्षीन चीन तथा निर्यातकों से आयात की नगण्य मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब्सिडी रोधी शुल्क की समाप्ति और आयात की मात्रा में वृद्धि के मामले में, घरेलू उद्योग आयात मूल्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होगा। ऐसी कीमतों से घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

**ज6. सब्सिडी रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग का संभावित प्रदर्शन**

99. राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को इन देशों से आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य किए जाने की संभावना है। वर्तमान आयात मूल्यों पर, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियों, नकद लाभों में कमी और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ के रूप में क्षति होने की संभावना है।

100. सब्सिडी रोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग का संभावित विश्लेषण

विवरण	इकाई	वास्तविक	संभावित	परिवर्तन
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	-
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	(***)%
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	(***)	(***)%
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	(***)	(***)%
नकद लाभ	₹/एमटी	***	(***)	(***)%
निवेश पर प्रतिफल	%	***	(***)	(***)%

**ज7. राजसहायता रोधी शुल्क लगाने के कारण ही घरेलू उद्योग का पुनरुद्धार।**

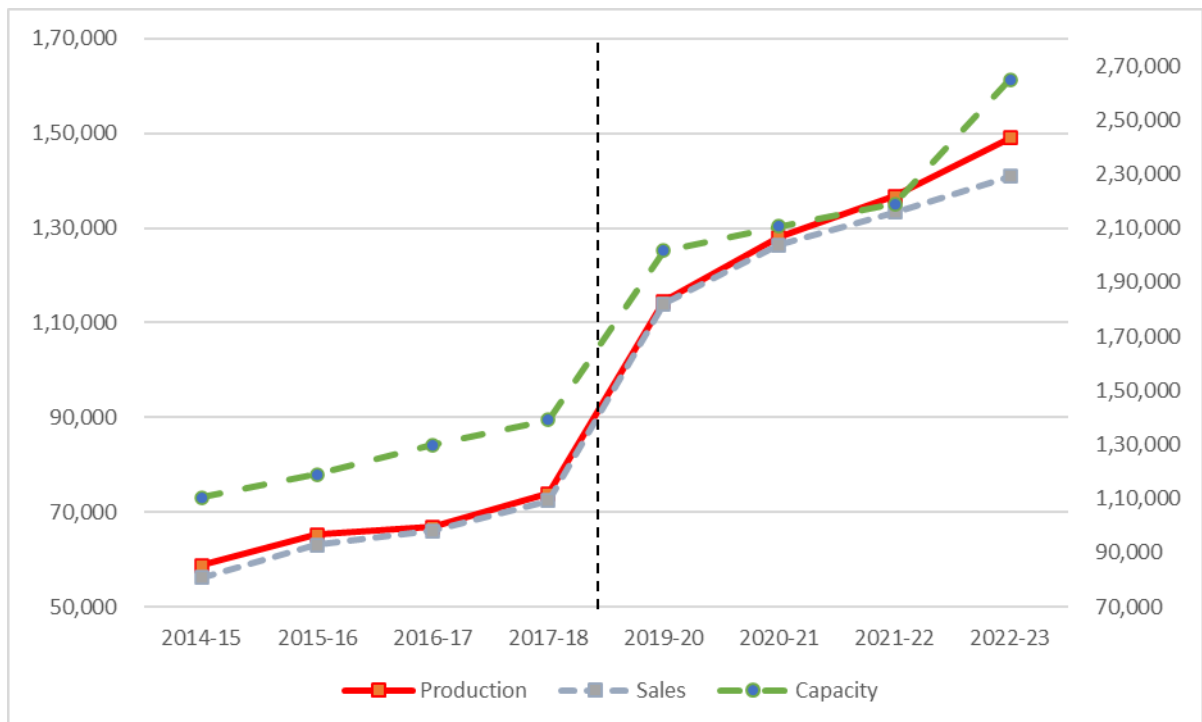
101. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की वर्तमान अवधि में राजसहायता-रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण जांच की मूल अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोनों अवधियों के बीच सुधार आयातों की मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप हुआ है।

विवरण	इकाई	मूल पीओआई	वर्तमान पीओआई	परिवर्तन
विषयगत आयात की मात्रा	एमटी	71,593	46,439	-35%
चीन से आयात	एमटी	43,059	129	-99.7%
वियतनाम से आयात	एमटी	28,535	46,310	62%
मांग	एमटी	***	***	***
क्षमता	एमटी	***	***	***
उत्पादन	एमटी	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***
आयात का बाजार हिस्सा	%	20-30%	10-20%	(50)-(60) %
भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी	%	60-70%	80-90%	20-30%
लाभ/हानि	₹/एमटी	घाटा	***	

102. मूल जांच की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार बिक्री में सुधार हुआ है। जांच के मूल दौर में जहां घरेलू उद्योग घाटे में चल रहा था, वहीं अब यह मुनाफा कमा रहा है।

#### ज8. सब्सिडी रोधी शुल्क लागू होने के कारण प्रदर्शन में सुधार

103. प्राधिकरण नोट करता है कि क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री के मामले में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में लागू होने के बाद और सब्सिडी विरोधी अवधि के दौरान काफी सुधार हुआ है।



104. चूंकि लागू राजसहायता-रोधी शुल्क के अभाव में, विषयगत आयात कम मूल्यों और बड़ी हुई मात्राओं पर भारत में प्रवेश कर सकते हैं, अतः राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

### ज9. हानिकारक कीमतों पर आयात

105. प्राधिकरण नोट करता है कि विषयगत आयात भारतीय बाजार में हानिकारक कीमतों पर प्रवेश किया है और शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम पर है।

#### झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

106. विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देशों से अवतरण मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

107. जहां तक वियतनाम के नए प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक टीवीएल द्वारा इस आधार पर व्यक्तिगत दर शुल्क प्रदान करने के लिए उठाए गए विवाद का संबंध है कि जांच में भाग लेने का यह उसका पहला अवसर है, प्राधिकरण नोट करता है कि टीवीएल ने वर्तमान जांच अवधि से एक वर्ष पहले भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया था।

108. टीवीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से पता चलता है कि टीवीएल ने वर्ष 2021-2022 में \*\*\* मीट्रिक टन और जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान \*\*\*मीट्रिक टन का निर्यात किया, जो भारत में कुल आयात का \*\*\*% और \*\*\*% और भारत में कुल मांग का \*\*\*% है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि भारत को निर्यात निर्दिष्ट अवधियों के दौरान टीवीएल के कुल उत्पादन का \*\*\*% है संबंधित देश से अन्य सहयोगी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात की तुलना में संख्या और प्रतिशत दोनों में काफी कम आंकड़ा। यह आगे नोट किया गया है कि टीवीएल का तीसरा देश निर्यात \*\*\* मीट्रिक टन था, जो इसके कुल उत्पादन का केवल \*\*\*%, इसकी घरेलू बिक्री का \*\*\*% और पीओआई के दौरान भारत में कुल आयात का \*\*\*% था।

109. चूंकि टीवीएल द्वारा भारत को निर्यात की गई मात्रा बहुत कम है, इससे यह संदेह पैदा हो सकता है कि जिस मूल्य पर टीवीएल ने भारत को निर्यात किया है, वह 'हेरफेर' मूल्य हो सकता है क्योंकि वर्तमान जांच सनसेट समीक्षा की है जिसमें संबंधित देश के उत्पादकों/निर्यातकों की कीमत का आकलन करना आसान है। अतः प्राधिकरण को निर्यात मूल्य की गहन संवीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि वह स्वयं को आश्वस्त कर सके कि टीवीएल से सीमित निर्यातों का निर्यात मूल्य वास्तव में इसकी कीमत को प्रतिबिम्बित करता है और यह संबंधित देश से आयातों पर प्रचलित सब्सिडी-रोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं हुआ है। खुद को फिर से आश्वस्त करने के लिए, प्राधिकरण ने टीवीएल के तीसरे देशों को निर्यात को देखा है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात मूल्य भारत को इसके निर्यात मूल्य के बराबर था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इस तरह के निर्यात मात्रा के साथ टीवीएल का निर्यात मूल्य 'रंगीन' नहीं है। तथापि, तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात भी बहुत कम है जैसा कि पहले पैरा में विचार-विमर्श किया गया था।

110. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, प्राधिकरण निर्यात की इतनी कम मात्रा के साथ भारत में टीवीएल के निर्यात मूल्यों को स्वीकार करने में असमर्थ है और इसलिए शुल्क की व्यक्तिगत दर के अनुदान के लिए टीवीएल के दावे को खारिज करता है।
111. सहकारी निर्यातकों के लिए उतराई तक की कीमत निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस विषय से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।
112. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुँच मूल्य और गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	विशेष	एनआईपी	लैंडेड प्राइस	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		अमरीकी डालर/एमटी	अमरीकी डालर/एमटी	अमरीकी डालर/एमटी	%	श्रेणी
1	वियतनाम					
क	सोनहा एसएसपी वियतनाम	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	स्टील 568 कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन. गण.					
क	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40

#### ज. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

113. प्राधिकरण ने जांच की कि क्या सीवीडी नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। इन नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ, राजसहायता प्राप्त आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या क्षति होने की संभावना हो, की जांच करनी अपेक्षित है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति के लिए राजसहायता प्राप्त आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारण लिंक की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकरण ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है या होने की संभावना है।

#### क. मांग में संकुचन

114. संबंधित वस्तुओं की मांग में प्रारंभ में गिरावट आई लेकिन उसके बाद क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। मांग में संकुचन का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई जानकारी नहीं है। मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है।

#### ख. खपत का पैटर्न

115. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए क्षति का कारण बताया जा सकता है।

**ग. प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तें**

116. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं, जो अधीन देशों से कम कीमत वाले आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

**घ. प्रौद्योगिकी में विकास**

117. संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।

**ङ. उत्पादकता**

118. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी नहीं आई है और इस प्रकार इसके कारण इसे कोई क्षति नहीं पहुंची है।

**च. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन**

119. घरेलू उद्योग ने निर्यात निष्पादन को घरेलू निष्पादन से अलग रखा है और इस प्रकार इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

**छ. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन**

120. इस क्षति के लिए कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पृथक किया है और सूचना प्रदान की है।

**ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे****ट1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ**

121. अन्य इच्छुक पार्टियों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई प्रस्तुतियां नहीं दी हैं।

**ट2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ**

122. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं

- क. आयातकों और उपयोगकर्ताओं ने आर्थिक हित प्रभावली में भाग नहीं लिया है या जवाब नहीं दिया है।
- ख. जवाब देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जो प्राधिकरण को यह निर्धारित करने की अनुमति दे सके कि शुल्कों को बंद करना जनहित में होगा या नहीं। इस संबंध में किसी सूचना का न होना यह दर्शाता है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं है कि इन शुल्कों का भारत में प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग. शुल्क जारी रहने से भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए अनुकूल बाजार स्थितियां पैदा होंगी क्योंकि इससे इस्पात आयात पर निर्भरता कम होगी।
- घ. यह उपभोक्ताओं के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो जो उचित मूल्य के आयातों के मुकाबले में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।
- ङ. भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- च. भारतीय उद्योग में उत्पादकों की संख्या 100 से अधिक है और शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में कोई एकाधिकार नहीं पैदा होगा।



- छ. भारतीय उद्योग खंडित है और भारत में इस तरह की वस्तुओं के अधिकांश उत्पादक एमएसएमई हैं और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कों को जारी रखना अनिवार्य है।
- ज. विषय वस्तुएं अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं हैं और इस प्रकार कर्तव्यों का प्रभाव, जो न्यूनतम है, अन्य उद्योगों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा।
- झ. विषय वस्तुओं का उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण में किया जाता है और इस उत्पाद के कारण लागत एक निर्माण परियोजना की कुल लागत का केवल 0.3% है। प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है।
- ञ. माल इटली, मलेशिया, अमेरिका और कोरिया आरपी जैसे विभिन्न अन्य देशों से आयात किया जा सकता है।
- ट. मूल जांच के बाद से मांग बढ़ने के बाद से शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ठ. कर्तव्यों के जारी रहने के मामले में, आउटगोइंग विदेशी मुद्रा को संरक्षित किया जाएगा, जिससे भुगतान का अनुकूल संतुलन होगा।

### ट3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

123. प्राधिकरण नोट करता है कि सामान्यतः शुल्क का उद्देश्य राजसहायता की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से अधीन देशों से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकरण मानता है कि सब्सिडी-रोधी शुल्कों के जारी रहने से भारत में उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है। हालांकि, सब्सिडी विरोधी उपायों के जारी रहने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, सब्सिडी-रोधी उपायों को जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि दी गई राजसहायता के कारण कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और विषयाधीन वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
124. जांच शुरू होने के बाद, प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पक्षों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। तथापि, प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग और वियतनाम के दो उत्पादकों नामतः सोन्हा एसएसपी वियतनाम एंड स्टील कंपनी लि द्वारा दायर किया गया था। इसके अलावा, संबंधित वस्तुओं और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने भी शुल्क की निरंतरता या समाप्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई है या कोई बयान नहीं दिया है।
125. प्राधिकरण नोट करता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि लागू कर्तव्यों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन में गिरावट आई है, या इस तरह की गिरावट हो सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण द्वारा संरचित और प्रमाणित जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के बावजूद, आर्थिक हित प्रश्नावली के जवाब में, उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जांच में भाग लेने से परहेज किया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकरण नोट करता है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उपायों को जारी रखने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
126. इस संबंध में, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं पर राजसहायता-रोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव को प्रस्तुत किया था। घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव लगभग 0.03% था।

विवरण	इकाई	दर
भूमि की लागत	₹ लाख	***
भवन निर्माण की लागत	₹ लाख	***
भवन की कुल लागत	₹ लाख	***
WSSTP की लागत	₹ लाख	***
उच्चतम सीवीडी लगाया गया	%	29.88%
सबसे कम सीवीडी लगाया गया	%	10.33%
कुल भवन में सीवीडी की लागत (उच्चतम)	₹ लाख	***
कुल भवन में सीवीडी की लागत (सबसे कम)	₹ लाख	***
उच्चतम सीवीडी के साथ प्रभाव	%	0-0.10%
सबसे कम सीवीडी के साथ प्रभाव	%	0-0.10%

127. देश में समान वस्तु की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि सस्सिडी-रोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल समान अवसर प्रदान करता है। ऐसा समान अवसर कई एमएसएमई कंपनियों को भारतीय बाजार में फलने-फूलने का मौका देगा। भारतीय उद्योग में भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। शुल्क लगाए जाने के बाद से मांग में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि शुल्कों ने आयात पर निर्भरता कम कर दी है और भारतीय उद्योग को बढ़ने का मौका दिया है।
128. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत में पर्याप्त क्षमता है। इससे पता चलता है कि प्रतिकारी शुल्क लगाने से देश आत्मनिर्भर बन गया है।
129. खंडित प्रकृति और बहु-उत्पादकों की उपस्थिति से भी घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। परिणामस्वरूप, प्रयोक्ताओं को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों और विषयगत वस्तुओं की आसान उपलब्धता का आश्वासन दिया जाएगा। आवेदकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि उत्पाद को अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।
130. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का प्रस्ताव यह निष्कर्ष निकालने का है कि शुल्क जारी रखने से उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और घरेलू बाजार में संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### ठ. पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियाँ

##### ठ1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

131. टीवीएल का तर्क है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 या काउंटरवेलिंग नियम कम निर्यात मात्रा के लिए व्यक्तिगत शुल्क अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्राधिकरण ने पिछले मामलों में व्यक्तिगत शुल्क दरें प्रदान की हैं, जैसे कि 2007 और 2008 में डीआई पाइप्स और सेफिट्रियाक्सोन सोडियम स्टेराइल के आयात के लिए भारत में केवल दो निर्यात लेनदेन होने के बावजूद। प्रतिवादी प्राधिकरण से व्यक्तिगत शुल्क दरों को देने में सुसंगत होने का अनुरोध करता है।

132. उपरोक्त सबमिशन के अलावा, टीवीएल प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि यदि व्यक्तिगत शुल्क दरों के लिए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे न्यू शिपर समीक्षा के साथ प्राधिकरण से संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

### ठ2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

133. जांच दल द्वारा गणना की गई एनआईपी अनावश्यक रूप से कम प्रतीत होती है। जांच के अधीन घरेलू उद्योग को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए उत्पादकों के रिकॉर्ड गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में संगठित क्षेत्र के मानकों से मेल नहीं खा सकते हैं। इसलिए, उनकी लागत को मानकीकृत नहीं किया जाना चाहिए और एनआईपी की गणना उनके वास्तविक लागत के आधार पर की जानी चाहिए।

### ठ3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

134. पीओआई में केवल दो लेनदेन के साथ निर्यातकों को सौंपे गए व्यक्तिगत कर्तव्यों के बारे में टीवीएल की चिंता के बारे में, प्राधिकरण नोट करता है कि टीवीएल द्वारा उद्धृत दोनों मामलों में, संबंधित पक्षों का पीओआई से पहले निर्यात का इतिहास था, और यह पीओआई के दौरान था कि उनके पास भारत को निर्यात के केवल दो लेनदेन थे। हालांकि, टीवीएल का एक्सपोर्ट वॉल्यूम पीओआई के दौरान और इससे पहले के वर्ष दोनों में कम था। इस परिस्थिति ने प्राधिकरण को यह पुष्टि करने की अनुमति नहीं दी कि टीवीएल की निर्यात कीमतें जोड़-तोड़ नहीं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने स्वयं को आश्वस्त करने के लिए निर्यात मूल्य की गहन संवीक्षा करने का प्रयास किया कि टीवीएल से सीमित निर्यातों का निर्यात मूल्य वास्तव में इसकी कीमत को दर्शाता है और संबंधित देश से आयात पर प्रचलित सब्सिडी रोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं हुआ है। खुद को फिर से आश्वस्त करने के लिए, प्राधिकरण ने टीवीएल के तीसरे देशों को निर्यात को देखा है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात मूल्य भारत को इसके निर्यात मूल्य के बराबर था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि इस तरह के निर्यात मात्रा के साथ टीवीएल का निर्यात मूल्य 'रंगीन' नहीं था। हालांकि, तीसरे देशों में टीवीएल का निर्यात भी बहुत कम था और इसलिए प्राधिकरण ने व्यक्तिगत शुल्क दर के अनुदान के लिए टीवीएल के दावे को खारिज कर दिया।

135. इसके अलावा, मूल जांच में, इच्छुक पक्षों के पास ऐसे डेटा या सूचना तक पहुंच नहीं होती है जो उन्हें अपने लाभ के लिए निर्यात मूल्यों में हेरफेर या प्रभावित करने में सक्षम बनाती हो। हालांकि, सनसेट रिव्यू जांच में, मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शुल्क सार्वजनिक डोमेन में होते हैं। यह जानकारी संभावित रूप से नए निर्यातकों को अपनी कीमतों में हेरफेर करने में सक्षम बना सकती है। टीवीएल द्वारा उद्धृत जांच की परिस्थितियाँ मूल जांच से संबंधित हैं और इसकी तुलना वर्तमान जांच से नहीं की जा सकती है जो एक सनसेट रिव्यू है। यदि यह मूल जांच होती, तो कम निर्यात मात्रा के लिए कीमतों के वास्तविक प्रतिबिंब का विश्लेषण करने के लिए इतनी गहन जांच की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि यह मामला सनसेट रिव्यू का है, जहां कीमतों पर सब्सिडी-विरोधी शुल्कों के प्रभाव के बारे में हितधारकों को पहले से ही पता है, इसलिए यह कहना कि कम निर्यात मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए और निर्यातक/उत्पादक को सीधे जैकेट फॉर्मूले के तहत शुल्क की एक व्यक्तिगत दर दी जानी चाहिए, उचित नहीं है।

136. गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) पर घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की गैर-हानिकारक कीमत की गणना एंटी-डॉपिंग (एडी) नियम 1995 के अनुलग्नक III के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जो यह प्रदान करता है कि घरेलू उद्योग के घटकों द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग का सर्वोत्तम उपयोग, (ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि में कच्चे माल के अकुशल उपयोग के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को कम करने के लिए पीओआई और पीओआई दरों पर ब्याज दरों पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए एनआईपी के निर्धारण की पद्धति को छूट देने के लिए एडी नियम 1995 में कोई प्रावधान नहीं है।

**ड. निष्कर्ष**

137. उठाए गए विवादों, हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुतियों और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग को सब्सिडी और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:
- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप्स हैं जिन्हें टैरिफ टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 73 के तहत टैरिफ कोड 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि संबंधित वस्तुओं का आयात एचएस कोड 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहता है।
  - ii. प्राधिकारी ने नोट किया कि मूल जांच में भाग लेने वाले एकमात्र चीनी उत्पादक ने वर्तमान समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया। इसी तरह, वियतनाम के कुछ उत्पादक जिन्होंने मूल जांच में भाग लिया था, उन्होंने भी वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। इसलिए, उन्हें वर्तमान सनसेट समीक्षा जांच में असहयोगी माना जाता है। हालांकि आयात डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि इन निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात विशिष्ट शुल्क आकर्षित करते हैं। इसलिए, मूल जांच में ऐसे भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों से किसी भी सहयोग के अभाव में प्राधिकारी उनके शुल्कों को व्यक्तिगत से अवशिष्ट श्रेणी में स्थानांतरित करने की कार्यवाही करता है।
  - iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन और वियतनाम से आयातित उत्पाद की वस्तु की तरह है।
  - iv. आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।
  - v. आवेदन में सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी जानकारी निहित थी और आवेदन में वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इसके अलावा, आवेदकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक और आवश्यक समझी जाने वाली सभी जानकारी प्रदान की।
  - vi. तथापि, वर्तमान समतुल्य शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित कारकों द्वारा स्थापित किया गया है
    - क. विषयगत वस्तुओं की मांग में कमी आई है, तथापि, आयातों में कमी मांग में कमी के अनुसार नहीं हुई है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में वियतनाम से आयात में वृद्धि हुई।
    - ख. भारत में आयात की मात्रा चीन से कम हो गई है और लागू सब्सिडी विरोधी शुल्क के कारण सीमित थी। इस तरह के सीमित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमत पर थे। ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि मात्रा नगण्य थी लेकिन वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, इन कम कीमत वाले आयातों से घरेलू बाजार में भारी मात्रा में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने की उच्च संभावना है।
    - ग. वियतनाम से आयात की मात्रा 2020-21 की तुलना में पीओआई में काफी बढ़ गई। 300 श्रृंखला के लिए वियतनाम की उतराई कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से नीचे है। वियतनाम से कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को मार्जिन पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
    - घ. सब्सिडी रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण हानि अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मांग में उत्पादन, क्षमता, बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। तथापि, पीओआई में क्षमता उपयोग, निवेश पर आय, नकद लाभ और पीबीआईटी में कमी आई है जिससे प्रतिशुल्क को जारी रखने की आवश्यकता प्रदशत होती है।

- ड. राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होने की संभावना है।
- च. विचाराधीन उत्पाद के लिए चीनी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता है। चीन पीआर में स्टेनलेस स्टील की मांग में गिरावट आई है। शुल्कों के रूप में अवरोध समाप्त हो जाने के बाद चीन के उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग भारत को संबंधित वस्तुओं के निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।
- छ. विषय देशों में उत्पादक तुर्की, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूएसए और ब्राजील में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना कर रहे हैं और इन देशों में निर्यात की मात्रा खो चुके हैं। अतः राजसहायता रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इन उत्पादकों द्वारा अपना निर्यात भारतीय बाजार में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
- ज. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम मूल्यों पर आयात किया जा रहा है। राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में, आयात मूल्य कम होने की संभावना है और इस बात की पूरी संभावना है कि वर्तमान शुल्कों के अभाव में ऐसे कम मूल्य वाले आयातों से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना होगी।

### द. सिफारिशें

138. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और चीन जन. गण. और वियतनाम सरकार सहित सभी इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और उन्हें सब्सिडी, क्षति, कारण लिंक, सब्सिडी की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित सूर्यास्त समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को आगे बढ़ाया जाना अपेक्षित है।
139. तदनुसार, प्राधिकरण चीन पीआर और वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जैसा कि नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाया गया है।

### शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73064000, 73066100, 73066900, 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90#	वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब	चीन जन. गण. अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी निर्माता	29.88

2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	29.88
3	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	सोनहा एसएसपी वियतनाम सोल मेंबर कंपनी लिमिटेड	शून्य
4	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	स्टील 568 कं, लिमिटेड	शून्य
5	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	जिया आन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड	11.96
6	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	उपरोक्त 2 से 4 के अलावा कोई भी निर्माता	11.96
7	-वही-	-वही-	वियतनाम और चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी निर्माता	11.96

*#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

140. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न पदनामित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, नामित प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi 15th June 2024

**FINAL FINDINGS****Case No. CVD/SSR-09/2023**

**Subject: Sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam.**

**1. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 7/23/2023-DGTR.—1.** An anti-subsidy investigation into imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”) was initiated by the Designated Authority on 9<sup>th</sup> August, 2018. Following a detailed investigation, the Designated Authority concluded that the subsidies provided by the Chinese Government and Vietnamese Government to the producers of the subject goods were countervailable in nature and the subject goods were exported from the subject countries at subsidized prices causing injury to the domestic industry. Consequently, the Authority recommended imposition of countervailing duty on imports of subject goods from the subject countries vide final findings No. 6/22/2018-DGAD dated 31<sup>st</sup> July 2019. The measures were implemented by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 4/2018 – Customs (CVD) dated 17<sup>th</sup> September 2019.

2. Pursuant to an application filed by the exporters of the subject goods, the Designated Authority initiated a limited mid-term review of the anti-subsidy duty vide Notification dated 11<sup>th</sup> February 2021 to examine the need for modification of scope of product under consideration. Following a detailed investigation, the Authority concluded that the product exclusion requested by the exporter was not warranted vide Final Findings No. 7/45/2020-DGTR dated 8<sup>th</sup> February 2022.
3. Stainless-Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi, and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat (hereinafter referred to as the “applicants” or “applicant associations”), filed an application before the Authority under Trade Notice 09/2021 dated 29<sup>th</sup> July 2021. This application, made on behalf of their members and producers of the subject goods in India, requested the initiation of a sunset review of the anti-subsidy duty concerning imports of Welded Stainless-Steel Tubes and Pipes originating in or exported from China PR and Vietnam. Forty (40) members of the applicants (hereinafter referred to as the “applicant domestic producers” or the “domestic industry”) submitted data in accordance with the requirements of Trade Notice 09/2021 dated 29<sup>th</sup> July, 2021.
4. In accordance with Section 9(6) of the Act, countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect upon the expiry of five years from the date of imposition. The Authority is required to review whether the expiry of the countervailing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of subsidization and injury. Furthermore, Rule 24(3) of the Rules provides as follows:

*“Any definitive countervailing duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition. The designated authority may upon coming to a conclusion, on a review initiated before that period either on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, make recommendation for extending the period of such imposition in accordance with provisions of section 9 of the Act.”*

5. In accordance with the above and based on a duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, the Authority is required to review as to whether the expiry of anti-subsidy duties is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury.
6. The applicants filed an application dated 31<sup>st</sup> July 2023, requesting initiation of sunset review of anti-subsidy duties imposed earlier and seeking continuation of anti-subsidy duties against imports of Welded Stainless-Steel Tubes and Pipes from China PR and Vietnam. The request was based on the grounds that imports of subsidized subject goods from Vietnam are causing material injury to the domestic industry and the expiry of the measures is likely to result in continuation of subsidization of the product under consideration and consequent injury to the domestic industry.
7. In view of a duly substantiated application with prima facie evidence of material injury to the domestic industry due to imports from Vietnam and likelihood of subsidization and injury due to imports from China PR and Vietnam, filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9(6) of the Act, read with Rule 24 of the Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 07/23/2023–DGTR, dated 30<sup>th</sup> September, 2023 to review the need for continued imposition of anti-subsidy duties in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and Vietnam and to examine whether the expiry of anti-subsidy duty on imports of subject goods from the subject countries is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry.

#### B. PROCEDURE

8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings No. 6/22/2018 -DGTR dated 17<sup>th</sup> September, 2019 by which the Authority had recommended imposition of anti-subsidy duty on imports of subject goods from the subject countries.
9. The procedure described herein below has been followed in the present investigation:
  - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants on behalf of the domestic industry contending injury due to imports from Vietnam and likelihood of continuation of subsidization and consequent injury to the domestic industry due to imports of product under consideration from the subject countries.
  - ii. The Authority notified the embassies of China PR and Vietnam in India about the receipt of the application before initiation the investigation in accordance with Rule 6(5).
  - iii. The Authority vide Notification No. 07/23/2023 dated 30<sup>th</sup> September 2023, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review of anti-subsidy duty on imports of the subject goods from the subject countries.
  - iv. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users in India and other interested parties, as per the information available, to inform them of initiation of the subject investigation in accordance with Rule 7(2) of the Rules.
  - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Governments of the subject countries through their Embassies in India, and to other interested parties who made a request therefore in writing in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
  - vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating sunset review investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 7(4) of the Rules. The Authority also issued economic interest questionnaire to all the interested parties and the concerned ministry.



- vii. The Authority sent a questionnaire to the Government of China PR (GOC) and the Government of Vietnam (GOV) seeking relevant information in the form and manner prescribed regarding various schemes/programs where countervailable benefits might have been conferred onto the producers/exporters in the subject countries. However, no response was filed by either Government of China PR or the Government of Vietnam.
- viii. The Authority forwarded the exporters' questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries:
- a. Emetal Company Ltd., China PR
  - b. Foshan Metalwell Co Ltd., China PR
  - c. Foshan Nanhai Zhouying Hardware Acc, China PR
  - d. Guangdong Foreign Trade Imp. & Exp. Co., China PR
  - e. Guangdong Sumwin New Material Group Co. Ltd., China PR
  - f. Guangfeng Steel Corporation, China PR
  - g. Haimen Senda Decoration Material Co., Ltd., China PR
  - h. Jiangsu New Qiuqing Stainless Steel Co., Ltd., China PR
  - i. Jieyang City Baowei Stainless Steel Co., Ltd., China PR
  - j. Low Metals Ltd., China PR
  - k. Minimetals Steel Co., Ltd., China PR
  - l. Okaya (Shanghai) Co., Ltd., China PR
  - m. Pohang (Zhangjiagang) Stainless Steel Processing Co., Ltd., China PR
  - n. Shandong Huaye Stainless Steel Products Co., China PR
  - o. Shanghai Hyss International Trading Co., Ltd., China PR
  - p. Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., China PR
  - q. Tsingshan Holding Group Shanghai International Trading Co., Ltd., China PR
  - r. Wuxi City Steel Co., Ltd., China PR
  - s. Wuxi Joyray International Corp, China PR
  - t. Xiamen Golden Huanan Imp. & Exp. Co. Ltd., China PR
  - u. Young Metal Co. Ltd., China PR
  - v. Yuyao Xingda Stainless Steel Co., Ltd., China PR
  - w. Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., China PR
  - x. Zhejiang Huashun Metal Materials Co., Ltd., China PR
  - y. Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd., China PR
  - z. Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
  - aa. Gia Anh Joint Stock Company, Vietnam
  - bb. Ha Anh Stainless Steel Company Limited, Vietnam
  - cc. Inox Hoa Binh, JSC, Vietnam
  - dd. Minh Huu Lien JSC, Vietnam
  - ee. Nam Cuong Metal Company Limited, Vietnam
  - ff. Oss Dai Duong International Joint Stock Company, Vietnam
  - gg. Sonha International Corporation, Vietnam
  - hh. Steel 568 Co., Ltd., Vietnam
  - ii. Tap International, JSC, Vietnam, Vietnam
  - jj. Tuan Dat Metal Company Limited, Vietnam
  - kk. Vinainox, Vietnam
  - ll. Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd., Vietnam
- ix. The Governments of the subject countries, through their Embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies of the subject countries along with the details of the known producers/ exporters.

- x. The following producers/exporters from the subject countries filed a response to the exporters' questionnaire:
  - a. Sonha International Corporation, Vietnam
  - b. Steel 568 Co., Ltd., Vietnam
  - c. TVL Steel Production and Construction Joint Stock Company, Vietnam
  - d. Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
  - e. OSS Daiduong International Joint Stock Company
  - f. Nam Cuong Metal Company Limited
- xi. The Authority forwarded a copy of the Notification to the known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information In response to the Notification, none of the importers/users have responded by filing questionnaire response.
- xii. The Authority issued Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject countries, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Response to Economic Interest questionnaire has been filed only by the applicants.
- xiii. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR's website, along with a request for all the parties to email the non-confidential version of their submissions to each of the interested parties.
- xiv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2019- 20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.
- xv. The applicants submitted that they did not have access to DGCI&S transaction-wise data and hence, the information regarding imports into India was provided as per the market intelligence. A request was made by the Authority to the Directorate General of Systems ("DG Systems") to provided transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority.
- xvi. The application for initiation of the present investigation was made by the applicant associations on behalf of the domestic industry under Trade Notice 09/2021. The application was filed by the domestic industry, accompanied by data from 18 entities. The Authority is cognizant of the fact that over 100 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) produce the subject goods across the country. The Authority sought to ascertain whether the trends observed in the data of the 18 companies were representative of the broader industry. To this end, the Authority requested additional data from companies affiliated with the associations. The analysis of this expanded data set revealed that all major economic parameters aligned with the trends identified in the initial data. Owing to the presence of large number of producers within the MSME sector in India manufacturing the subject goods, and the complexity involved in handling large amount of data the Authority opted for sampling in the present investigation.
- xvii. The Authority sought further information from the sampled domestic producers to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the sampled domestic producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the sampled domestic producers in its analysis in the present case.
- xviii. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

- xix. The non-injurious price has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- xx. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 14<sup>th</sup> May 2024. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xxi. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this disclosure statement.
- xxii. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this disclosure statement to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xxiii. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis
- xxiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non- cooperative and recorded this disclosure statement on the basis of the facts available.
- xxv. \*\*\* in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is **1 US\$ = ₹ 81.06.**

## C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

### C.3 SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

10. One of the interested parties requested the Authority to adopt the PCNs considered in the original investigation in the ongoing investigation, which are provided below
  - a) 200 Series
  - b) 300 Series
  - c) 400 Series

## C2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration or like article.
  - a. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as defined in the original investigation.
  - b. The product under consideration is Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes. The subject goods are made up of 200, 300 and 400 series. Accordingly, the PCN has been proposed based on the raw material used.
  - c. The subject goods produced by the domestic industry are like article to product under consideration imported from the subject countries.

**C3. Examination by the authority**

12. The product under consideration in the present investigation is Welded Stainless Steel Tubes and Pipes. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation.
13. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff codes 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The domestic industry has submitted that the subject goods are also being imported under the HS Codes 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
14. Based on the comments received from the interested parties, the Authority found it appropriate to adopt PCN methodology for fair comparison. The following PCNs were finalized by the Authority.

SN	PCN Parameter (Grade of Steel)	Code
1.	200 series	2S
2.	300 series	3S
3.	400 ries	4S

15. The PCNs finalized in the present investigation are identical to that of original investigation. Therefore, the Authority holds that the product under consideration is the same as in the original investigation i.e., “welded stainless steel pipes and tubes”.
16. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.

**D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING****D1. Submissions by the other interested parties**

17. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing.
- The present investigation should not have been initiated since the applicant domestic producers do not account for 25% of the total Indian production. The Authority consistently applies test of standing in terms of Rule 6(3)(a) in sunset reviews.
  - None of the domestic producers constituting domestic industry have filed Annexure I in accordance with Trade Notice 09/2021. Accordingly, the present investigation should be terminated immediately.
  - The Authority may not accept the response submitted by the domestic producers voluntarily since such producers may be those with high cost of sales which are suffering injury on account of internal reasons. Trade Notice 09/2021 prescribes sample selection based on statistically valid techniques in order to ensure fairness and transparency.

**D2. Submissions by the domestic industry**

18. The following submissions have been made by the applicants with regard to the domestic industry and standing:
- The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat under Trade Notice 09/2021 on behalf of the domestic industry.

- b. The Indian industry is composed of more than 100 producers. 40 members of the applicant associations have filed data for the purpose of the present investigation.
- c. As opposed to the contention of the other interested parties, at the time of filing the application, the applicant domestic producers accounted for more than 25% of the total Indian production.
- d. While 18 companies filed data at the time of filing the application, post filing 22 more companies provided information sought by the Authority thereby increasing the share of the domestic producers to 50% of the total Indian production.
- e. The applicant domestic producers have not imported the product under consideration from the subject countries and are not related to any exporters/ importers.
- f. the total Indian production has been determined based on raw materials supplied for the production of the subject goods as estimated by JSSL, one of the largest Indian producers of upstream product catering to approximately 70% of the domestic demand.
- g. Five sampled producers as well as seven other producers have filed complete cost data for the purpose of the present investigation. The Authority may choose to add any of the volunteering producer for their micro analysis.
- h. As opposed to the contention of the other interested parties, the present investigation is a sunset review initiated under Rule 24 of the Anti-Subsidy Rules. As per the amended rules, Rule 6 is not applicable to sunset review and there is no requirement to establish standing.

### D3. Examination by the Authority

19. The application for initiation of the present review has been filed by two registered associations of the producers of the subject goods in India under Trade Notice 09/2021. The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi and Stainless-Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat on behalf of the domestic industry.
20. The Authority notes that the present investigation involves producers in MSME segment. The Indian industry manufacturing the subject goods is fragmented in nature and there are more than 100 producers of the subject goods in India.
21. The applicants have submitted that since there are a number of producers in India, they do not have access to the total production of the subject goods in India. In order to determine the total Indian production, the Authority has relied on the information filed by Jindal Stainless Steel Limited (“JSSL”). As per the information on record JSSL is the largest supplier of raw material, that is, stainless-steel coils for the production of the subject goods in India. JSSL accounts for \*\*\*% of the market share of the demand of raw material in India. JSSL has supplied \*\*\* MT of raw material in India during the period of investigation. In order to determine the total Indian production, the Authority has considered the SION norms of 1.05.

Particulars		Quantity (MT)
Coil Supplied by Jindal	A	***
Coil supplied by others	$B = A/70\% * 30\%$	***
Total Coil supplied	$C = A+B$	***
Estimated Indian production*	$D = C/1.05$	***
Range	MT	2,50,000-3,50,000

\*consumption norm of 1.05

22. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term ‘domestic industry’ may be interpreted as referring to the rest of the producers”.

23. Regarding the submissions from other interested parties asserting that Rule 6 is applicable to the current investigation, the Authority notes that since the present review is being conducted under Rule 24, Rule 6 does not apply. Rule 24 is as under:

(1) Any countervailing duty imposed under section 9 of the Act shall remain in force so long as and to the extent necessary, to counteract subsidisation, which is causing injury.

(2) The designated authority shall review the need for continued imposition of the countervailing duty, where warranted on its own initiative or upon request by any interested party who submits necessary information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive countervailing duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, when it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said countervailing duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(3) Any definitive countervailing duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition. The designated authority may upon coming to a conclusion, on a review initiated before that period either on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, make recommendation for extending the period of such imposition in accordance with the provision of section 9 of the Act.

(4) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

[Provided that notwithstanding anything contained in rule 19, such review shall be

completed at least three months prior to expiry of the countervailing duty under review].

[(5) Subject to sub-rule (4), the provisions of rules 7,8, 9,10,11,12,13,18,19,20,21 and 22 shall apply mutatis mutandis apply in case of review.]

24. The other interested parties have argued that the data submitted voluntarily by certain producers should not be used, as it may lead to data distortion. The Authority notes that when the number of producers is very large and more than 100 in number and these producers are mostly MSMEs and fragmented. The domestic industry has submitted injury information of 18 entities which was duly examined. Further, in order to substantiate their claim they have voluntarily submitted the data related to injury parameter of 22 more entities. On further examination, the Authority notes that the injury trend found in case of 18 entities are mostly similar to that of 22 additional entities and trend is also similar for that of 40 entities combined together.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E1. Submissions by other interested parties**

25. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

a. The applicant associations have not filed documents as per the requirement of Trade Notice 09/2021. In case such documents have been filed, the same may be provided to the other interested parties along with an opportunity for oral hearing.

b. The applicants have claimed excessive confidentiality as sales value, list of members of associations who have supported or opposed the investigation has been claimed confidential. According to trade notice 10/2018, the domestic industry has to disclose actual information in case of multiple producers. The principles laid down in the Trade Notice are applicable to anti-subsidy investigation as well. Confidentiality should not be granted automatically but a thorough examination of the same is required as held by the Supreme Court in *Sterlite Industries (India) Ltd. V. Designated Authority*.

- c. The applicants must show good cause in order to claim confidentiality as held by the Appellate Body in EC – Certain Iron or Steel Fasteners from China. The Authority may direct the domestic industry to file a proper non-confidential version of the petition as instructed in investigation on clear float glass. A fresh hearing may be granted after proper NCV of the application is filed by the applicants.

## **E2. Submissions by the domestic industry**

26. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
  - a. TVL Steel Construction and Joint Stock Company, Sonha SSP Vietnam and Steel 568 Co. have claimed blanket confidentiality regarding its ownership structure, shareholders, affiliate companies, nature of activities performed by affiliated entities, whether it has purchased inputs from affiliated/ government entity for producing subject goods.
  - b. TVL Steel Construction and JSC has claimed that it has not applied/ availed benefit for any import duty exemption for raw material, the information provided has been claimed confidential. Appendix-1 has been claimed confidential.
  - c. As opposed to the contention of the other interested parties, documents of associations cannot be disclosed as they contain business proprietary information which cannot be shared with the other interested parties.
  - d. The comments on confidentiality filed by the other interested parties are belated in nature as the same have been filed post 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the petition.
  - e. While the applicants have disclosed aggregate actual information with regard to volume parameters, price parameters are confidential business sensitive information disclosure of which will provide undue benefit to the competitors.

## **E3. Examination by the authority**

27. With regard to confidentiality of the information, the Rule 8 of the Countervailing Duty Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule(2) of rule 14, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19, copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

28. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of the submissions with each other through e-mails.

29. The other interested parties have contended that the applicants have not shared the documents of the associations. The Authority notes that the documents of the associations contain minutes of meetings, by-laws of the association as well as the memorandum of association which contain business proprietary information and cannot be disclosed to the other interested parties.
30. As regards confidentiality on sales value, the Authority notes that the sales value consists of sales volume and price. These are business proprietary information and its confidentiality needs to be maintained in order to compete with the other producer in the market. The Authority notes that disclosure of such information will provide undue advantage to the other interested parties. Therefore, the Authority has accepted the claim of confidentiality over such information.

## **F. Miscellaneous issues**

### **F1. Submissions by other interested parties**

31. No miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.

### **F2. Submissions by the domestic industry**

32. The domestic industry has not made any miscellaneous submissions.

## **A. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN**

### **A.1 Views of other interested parties**

33. The other interested parties have made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin issues:
- i. Since the producer/exporter has fully cooperated in the investigation, the margins must be determined as per the response filed and an individual duty may be granted to it.
  - ii. The exporter did not participate in the original investigation as it started commercial production in 2019-20 and exported to India in 2021-22. This is the first opportunity of participation.
  - iii. A new exporter is eligible for individual duty in a sunset review which is evident from the fact that the Authority has requested information from all interested parties including new exporters via the initiation notification. In a number of investigations such as those on imports of VSF, Graphite Electrodes, NFY, Aluminium Foil, NBR, NTCF and Jute, the Authority has prescribed individual duties to producers for first time in a sunset review. The CESTAT in Indian Graphite Manufacturers Association V. DA held that the Authority can fix anti-dumping duty for new exporters in a sunset review.
  - iv. A sunset review conducted by the Authority is akin to original investigation as held by the CESTAT in Robin Resources V. Designated Authority. Since the Authority in the present investigation is examining all parameters relevant for determination of subsidies, there is no rationale for not granting individual rate of duty to the new exporter.
  - v. The duty can be imposed to countervail any subsidy granted by the government of the exporting producers / exporters, not on subsidy granted by the government of a third country.
  - vi. Most Indian producers of the subject goods also import raw materials from China PR. Any claims of pass through of benefits would mean that the Indian producers are also getting subsidy on the raw materials imported from China PR.
  - vii. The claim of pass through of subsidy was made in the original investigation and was not accepted by the Authority.

### **A.2 Views of the domestic industry**

34. The domestic industry has made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin issues:
- i. The governments of the subject countries have provided significant support to the steel industry in the form of various subsidies.



- ii. The benefits under some of the schemes are non-recurring and must be examined over the average useful life for the subject goods.
- iii. Only the government can provide detailed information related to whether a said scheme is countervailable or not. An exporter can only provide information on whether any benefit was received or not.
- iv. In anti-subsidy investigation concerning imports of Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products from China, which is the raw material for the subject goods, the Authority concluded that the Government of China provides various countervailable subsidies.
- v. The Government of China has formulated various policies to support the iron and steel industry which has lead to overcapacities and excess production. This has even spilled over to foreign producers in Vietnam, that have exported subsidized goods to India.
- vi. No response has been received from the Government of China or Chinese producers/exporters.
- vii. In the absence of any information the Authority can undertake examination based on information available.
- viii. Since the continuation of various programs has not been contested, the new schemes alleged in the present investigation must not be investigated and the examination of subsidies in China may be restricted to only continuation of existing duty.
- ix. The holding company and the sister company of Gia Anh Hung Yen have not filed a response in the current investigation.
- x. The Authority may call for information on the affiliate entities.
- xi. The response filed by the responding producer should be rejected since complete details of the subsidies received cannot be obtained in case of non-participation of affiliated companies.
- xii. The producer has suppressed relevant information and has failed to provide a complete response, rendering its response fit for rejection.
- xiii. The import duty exemptions on inputs for exported products are not countervailable as long as the exemption is extended to the production of exported products only.
- xiv. The Government of China must have a system in place to confirm the inputs consumed for exported products. If such a system does not exist or is not applied effectively, it will lead to countervailing of the entire amount of the exemption.
- xv. The Authority should quantify the subsidy margin based on the best facts available.
- xvi. In other jurisdictions, where the Government of the exporting country does not cooperate, the investigating authorities rely on the facts available and determine the countervailability of the schemes.
- xvii. Some of the exporters / producers have failed to respond to Part - II of the questionnaire response.
- xviii. New subsidies alleged in this investigation need to be investigated in case of producers / exporters with zero percent margin in the original investigation.
- xix. The exporters have not shown that the information or evidence provided by the domestic industry is not accurate. The domestic industry has provided sufficient evidence required for initiation.
- xx. The subsidies provide to the producers of steel products, which has been found countervailable by the Authority in its findings in Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products from China have spilled over to foreign producers, even those in Vietnam, allowing such producers to export the goods to other countries, including India, at uncompetitive prices.

### **A.3 Examination by the Authority**

35. The application filed by the domestic industry provided *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies in the subject country on the subject good. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the governments of China and Vietnam, through written communications and consultations, to provide relevant information concerning the existence, operations and administration of various subsidy schemes contended by the applicants, countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM

and Indian Rules, and benefits availed by the producers/exporters of the subject countries under these schemes. The Authority notes that the Government of China has neither filed the response to the questionnaire, nor has provided any information relevant to various subsidy schemes. The Government of China has, thus, failed to co-operate with the Authority in the present investigation. As the Government of China has not extended the required co-operation, the Authority is constrained to proceed with the best available information for the purpose of the present disclosure statement. The response filed by Government of Vietnam has been taken on record and examined by the Authority.

36. The present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence. Post initiation, the producers/exporters of the subject goods were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of the alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any. However, no producers / exporters of the subject goods from China have filed questionnaire responses whereas the following producers/ exporters of the subject goods from Vietnam have filed questionnaire responses:

- i. Steel 568 Co. Limited
- ii. Sonha SSSP Vietnam Company Limited
- iii. TVL Steel Production and Construction Joint Stock Company (TVL)
- iv. Gia Anh Hung Yen Co., Limited (Gia Anh)
- v. Nam Cuong Metal Company Limited (Nam Cuong)
- vi. OSS Daiduong International Joint Stock Company (OSS)

37. The domestic industry has alleged that producers/exporters of the subject goods are receiving countervailable subsidies under the following programs of various levels of governments and they have been classified under six broad categories: grants, tax and VAT incentives, preferential loans and lending / financing, export financing and export credit, provision of goods at less than adequate remuneration, and equity infusions.

### **A.3.1 Subsidies in respect of China PR**

38. With respect to China, the Authority has initiated the investigation against the following schemes:

- i. *Schemes identified as provision of Goods and Services at Less Than adequate remuneration*
  - a. Provision of Water for Less than Adequate Remuneration
  - b. Hot Rolled Steel (HRS) provided by Government at less than adequate remuneration.
  - c. Provision of Cold-Rolled Steel for Less Than Adequate Remuneration (LTAR)
  - d. Government Provision for Steel Scrap for Less than Adequate Remuneration
  - e. Land use rights provided at less than adequate remuneration
  - f. Land Use Rights for SOEs
  - g. Provision of Nickel/Nickel Pig Iron for LTAR
  - h. Provision of Ferrochrome/Chromium for LTAR
  - i. Provision of Coking Coal for LTAR
  - j. Iron Ore at LTAR
  - k. Electricity at LTAR
  - l. Export restrictions on Coke
  - m. Provision of Land-Use Rights for LTAR – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs
- ii. *Schemes identified as Tax and Vat Incentives*
  - a. Tariff and VAT Exemptions for imported equipment
  - b. Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies.
  - c. Tax concessions for central and western regions
  - d. Tax preference available to companies that operate at a small profit
  - e. Enterprise income tax rate reduction in the tianjin port free trade zone
  - f. Tax credit concerning the purchase of special equipment

- g. Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)
  - h. Preferential tax policies for FIEs established in the pudong area of shanghai
  - i. Income tax reduction for enterprises with foreign investment and foreign enterprises established in special economic zones
  - j. Tax policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
  - k. Preferential income tax policy for the enterprises in the northeast region
  - l. Income tax refund for re-investment of FIE profits by foreign investors
  - m. Reduced tax rate for productive FIEs scheduled to operate for a period not less than 10 years
  - n. Income tax reduction for advanced technology FIEs
  - o. Preferential tax policies for FIEs and foreign enterprises and certain domestically- owned companies which have establishments or places in china and are engaged in production or business operations purchasing domestically produced equipment's
  - p. Preferential tax policies for the research and development of FIEs
  - q. VAT refunds for FIEs purchasing domestically - produced equipment
  - r. Tax reductions for technology or knowledge-intensive FIEs
  - s. Shanghai municipal tax refund for high-tech achievement commercialization projects
  - t. Local income tax and reduction program for the productive FIEs
  - u. Local income tax exemption and/or reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
  - v. Industrial parks promoting growth of steel industry
  - w. Dividend exemption between qualified resident enterprises
  - x. Preferential tax policies for FIEs established in the coastal economic open areas and in the economic and technological development zones
- iii. *Schemes identified as Preferential Loans and Lending*
- a. Credit guarantee by GOC
  - b. Preferential lending (including policy loans)
  - c. Preferential export financing from the Export-Import Bank of China
  - d. Preferential loans for SOEs
  - e. Allowance to pay loan I nterest
- iv. *Schemes identified as Export Financing and Export Credit*
- a. Export Seller's Credit
  - b. Export Buyer's Credit
  - c. Export Credit Insurance Subsidies
  - d. Other export financing from State Owned Banks
- v. *Schemes identified as Equity Infusion*
- a. Debt for equity swaps
  - b. Equity infusions
  - c. Unpaid dividends
  - d. Debt Forgiveness
  - e. Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring
- vi. *Schemes identified as Grants*
- a. Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products
  - b. Special fund for energy saving technology reform
  - c. Direct Government Grants given by Jiangsu Province
  - d. Grants to Baoshan Steel
  - e. Grants for Antidumping Investigations
  - f. Superstar Enterprise Grant

- g. Research & Development (R&D) Assistance Grant
  - h. Export Assistance Grant
  - i. Grants for Listing Shares
  - j. Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province
  - k. Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
  - l. Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
  - m. Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair
  - n. International Market Fund for Export Companies
  - o. Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
  - p. State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
  - q. Treasury Bonds Loans or Grants
  - r. Provincial Government - Equipment Grant
  - s. Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City
    - i. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
    - ii. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
    - iii. Grants under Excellent New Products/Technology Award
    - iv. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
    - v. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
    - vi. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
    - vii. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
  - t. Grants provided by Hebei Province
    - i. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
    - ii. Government of Shijiazhuang City Export Award
  - u. Various grants provided to Shandong Province
    - i. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers
    - ii. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy Saving Technology
    - iii. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
    - iv. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries
  - v. Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
  - w. Shanghai Municipal Subsidy to Coal-Fired Power Plants for Emissions Reduction
- vii. *Schemes identified as provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration*
- a. Purchase of Goods by the Government for higher than adequate remuneration

39. The principle of judicial economy allows the Authority to refrain from undertaking a detailed investigation in respect of those programs that were determined to be countervailable in the original investigation. The Authority has to examine whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies. However, the Government of China and the exporters from China PR have failed to co-operate and provide any response or comments. On the other hand, the domestic industry has made submissions demonstrating that the producers and exporters in China continue to avail the benefit of such countervailable subsidies. Thus, in view of the absence of any evidence presented by the government of China or its producers/exporters on whether such schemes have been withdrawn or not and the submissions by the domestic industry, the Authority concludes that the subsidy schemes countervailed in the original investigation continue to exist in China and provide benefit to the producers/exporters of the subject goods, based on the facts available.

40. In the sunset review investigation, the primary focus is to determine the likelihood of the continuation or recurrence of subsidies and the resultant injury. Unlike the original investigation, where it is necessary to establish and quantify current subsidy or injury margins to apply the principle of the lesser duty rule and accordingly determine the rate of duties, the present analysis centers on the likelihood of these factors and the continuation of already existing duties. Consequently, in the present circumstances where there are no new or contrary facts adduced before the Authority, the Authority exercises judicial economy concerning these schemes previously addressed and deemed countervailable in the original investigation. Thus, the existing subsidy margins are to be maintained and the Authority thereby restricts itself from repeating the exercise of detailed examination of subsidy schemes afresh for the subject sunset review investigation.

#### **New Programs alleged by the domestic industry in the present investigation**

41. The domestic industry has contended that there is one more countervailable scheme “Export Credit Insurance Subsidies” which provides benefit to the exporter / producers, thereby allowing them to sell at lower prices. No information has been provided by the producers/exporters or GOC about this scheme. Further, the domestic industry has also not provided sufficient information with regard to this program in order to quantify the benefit received by the producers / exporters from the subject country. In light of absence of sufficient information, the Authority does not consider it appropriate to examine countervailability of the new subsidy program alleged. Accordingly, the new program has not been examined for the purpose of the present investigation.
42. In absence of any response from producers / exporters and GOC, the Authority is constrained to rely on facts available on record, including the findings of the Authority in the original investigation as well as the information/evidence provided by the domestic industry during the course of the investigation. Therefore, the Authority continue to holding the above-mentioned programs as countervailable on the basis of its findings in the original investigation. Thus, the Authority has determined the subsidies equivalent to the subsidy margin quantified in the original investigation.

S.NO.	Name of Scheme	CVD Margin	Range
1.	Grants	***	0-10
2.	Tax and VAT Incentives	***	0-10
3.	Preferential lending	***	0-10
4.	Provision for goods and services at LTAR (A+B+C)	***	30-40
A.	Electricity at LTAR	***	0-10
B.	Land use rights provided at LTAR	***	0-10
C.	Raw Material at LTAR	***	20-30
	Total Subsidy Margin	***	30-40

#### **A.3.3 Subsidies in respect of Vietnam**

##### **Schemes previously found as countervailable in the original investigation**

43. With respect to Vietnam, the Authority has initiated the investigation against the following schemes:
- i. *Schemes identified as Tax Incentives and Exemption*
    - a. Import duty exemption or reimbursement for raw material
    - b. Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset
    - c. Exemption on corporate income tax for enterprises
    - d. Enterprise Income Tax Exemption under Chapter III of the Law on Enterprise Income Tax
  - ii. *Schemes identified as Export Financing and Export Credit*
    - a. Preferential Lending for investors
    - b. Export Promotion Program
  - iii. *Schemes identified as Investment Incentives*
    - a. Preferential lending to exporters
    - b. Assistance to Small-Medium Enterprises

- c. Interest rate of the investment credit loans
  - d. On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.
- iv. *Schemes identified as Benefits from Banks*
- a. Export credits from Vietnam Development Bank
  - b. Export financing activity by Vietin Bank
  - c. Financial Guarantees by Vietin Bank
  - d. Export Support Credit
- v. *Schemes identified as being provided in Specific Zones*
- a. Land preference for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones
- vi. *Schemes identified as Incentives on Use of Utilities*
- a. Exemptions or reduction on water rent
  - b. Government provision of land for less than adequate remuneration and exemption or reductions from land rents
44. In the original investigation, the Authority found the following programs to be countervailable.
- I. Schemes identified as tax incentives and exemptions**
1. Program No 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)
  2. Program No 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material
  3. Program No. 3: Exemption on corporate income tax for enterprises
- II. Schemes identified as export financing and export credit**
4. Program No 5: Preferential lending to exporters
  5. Program No 6: Export Promotion Program
  6. Program No 7: Export credits form the Vietnam Development Bank
  7. Program No. 8: Export Support Credit
- III. Schemes identified as investment incentives**
8. Program No. 9: Preferential Lending for investors
  9. Program No. 10: Interest rate of the investment credit loans
  10. Program No. 11: On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.
- IV. Schemes Identified as benefits from banks**
11. Program No. 13: Financial Guarantees by Vietin Bank
- V. Schemes Identified for being located in specific zones**
12. Program No 14: Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142
- VI. Schemes Identified for incentives on use of utilities**
13. Program No. 15: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents

**Schemes found as countervailable in the subject investigation**

45. The Authority notes that the applicants have primarily alleged likelihood of continuation/ recurrence of subsidization and consequent injury. Therefore, the Authority in the subject investigation, has focused on determination of the likelihood of the continuation or recurrence of subsidies and the resultant injury in the event of cessation of current duties.
46. The Authority acknowledges that in the initial investigation, schemes held countervailable were also found to benefit the participating exporters/producers. In the ongoing sunset review investigation, participating exporters/producers contended that they did not receive any benefits from the alleged schemes. However, no substantial evidence to establish that they have discontinued to avail the benefits from the countervailed schemes is provided to the Authority. Moreover, the Government of Vietnam (GOV), in their submissions have specifically asserted that there have been no discontinuation of the alleged programs and also there are no

anticipated changes in the said programs. Consequently, in the present circumstances where there are no new or contrary facts adduced before the Authority, the Authority exercises judicial economy concerning these schemes previously addressed and held countervailable in the original investigation. Thus, the existing subsidy margins are to be maintained and the Authority thereby restricts itself from repeating the exercise of detailed examination of subsidy schemes afresh for the subject sunset review investigation.

47. The Authority observed that the questionnaire response submitted by Nam Cuong Metal Company Limited was severely lacking and did not adhere to the format specified by the Authority. Furthermore, it failed to provide any pertinent information, documentation, or evidence regarding the programs under investigation. Consequently, the Authority was compelled to rely on the best available facts for the exporter/producer in question, as outlined in Rule 7(8) of the CVD Rules, 1995.
48. Exporter/producer OSS Dai Duong International Joint Stock Company have stated that they did not export to India during the period of investigation. This claim has been verified by the Authority using DG systems data. Further, to investigate whether OSS was still availing the benefits of the subsidy schemes countervailed in the original investigation during the POI of the present investigation, the investigation team requested OSS to participate in the remote desk verification to verify its response. However, OSS failed to respond to this request. This wilful omission on part of OSS has hindered the Authority's ability to verify the information provided. Consequently, the Authority has calculated OSS's subsidy margin based on the facts available, as stipulated under Rule 7(8) of the CVD Rules, 1995.
49. Gia Anh Joint Stock Company had claimed that it did not export the subject goods to India during the POI. This claim was verified by the investigation team through DG Systems data. Gia Anh has filed complete exporter questionnaire response. To verify whether Gia Anh had taken benefit in the POI of the present investigation under any of the schemes countervailed in the original investigation, the investigation team requested to participate the above mentioned exporter/producer in remote desk verification meeting for validation of its response. During the remote desk verification Gia Anh claimed that it had not taken any benefit under any of the schemes. Investigation team posed several queries to Gia Anh regarding the subsidy schemes. While examining availment of subsidies under Program no 3 and 14, the investigation team put forward the Investment Policy Certificate issued by People's Committee of Hung Yen Province to Gia Anh. According to this Certificate, Gia Anh is entitled to various incentives aimed at fostering the production of high-grade stainless steel products in Vietnam. Further, article 4 of the Certificate specifies that this entitlement remains effective until November 13, 2052. Gia Anh was asked to demonstrate that it had not availed any benefit under the schemes based on its financial statements. However, the representatives of the exporter company failed to provide substantial evidence to support their claim that the company did not continue to avail benefits. As the investigation team was also not able to find any evidence concerning an increase in the amount of benefits conferred under the countervailed schemes the Authority has continued with the subsidy margins as determined in the original investigation.

#### **New Programs alleged by the domestic industry in the present investigation**

50. Additionally, the domestic industry has contended that there are three countervailable programs providing benefits thereby allowing producers in Vietnam to sell at a lower price. The list of such new programs is provided below:
- Exemption on Import for Exported Goods
  - Enterprise Income Tax Exemption under Chapter III of the Law on Enterprise Income Tax
  - Assistance to Small- Medium Enterprises
51. The Authority notes that while the domestic industry has alleged the existence of new programs as mentioned above, the allegations have not been substantiated by relevant and material evidences. Hence, the Authority is not in a position to examine the countervailability of the newly alleged programs.

<b>P. No.</b>	<b>Name of the Program</b>	<b>Son Ha SSP Vietnam</b>	<b>Steel 568 Co.Ltd</b>	<b>Residual</b>
P.1	Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)	NIL	NIL	0-5%
P.3	Exemption on corporate income tax for enterprises			

P.2	Import duty exemption on reimbursement for raw material	NIL	NIL	NIL
P.5	Preferential lending to exporters	NIL	NIL	0-5%
P.6	Export Promotion Program	NIL	NIL	0-5%
P.7	Export credits form the Vietnam Development Bank	NIL	NIL	0-5%
P.8	Export Support Credit	NIL	NIL	0-5%
P.9	Preferential Lending for investors	NIL	NIL	0-5%
P.10	Interest rate of the investment credit loans	NIL	NIL	0-5%
P.11	On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.	NIL	NIL	0-5%
P.13	Financial Guarantees by Vietin Bank	NIL	NIL	0-5%
P.14	Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142	0-5%	0-5%	0-5%
P.15	Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents			
Other	Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset	NIL	NIL	0-5%
<b>Total Subsidy Margin %</b>		***	***	***
<b>Total Subsidy Margin (Range %)</b>		<i>De-minimis</i>	<i>De-minimis</i>	<b>10-20%</b>

#### G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF SUBSIDIZATION AND INJURY

##### G1. Submissions by other interested parties

52. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury, causal link and likelihood of subsidization and injury:
- The domestic industry has neither suffered injury nor there is any likelihood of continuation or recurrence of injury. This is evident from the fact that the capacities, production, domestic sales, domestic selling price, PBIT, cash profits and return on investment of the domestic industry have increased.
  - There is no injury or likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry due to imports from the respondents as the import price of the respondents has increased and was the highest during the period of investigation. Since no duty was imposed on the respondents, there will be no change in pricing behaviour even in case of no anti-subsidy duty in force.
  - While major imports from Vietnam are from sources exempt from duty, the economic parameters of domestic industry including domestic sales, selling price and profits have improved. Since the domestic



industry has not suffered injury due to such imports, there is no likelihood of injury in case of cessation of anti-subsidy duty in force.

- d. The injury suffered by the domestic industry, if any, is only due to imports from China. This is due to the fact that the Chinese imports are undercutting the prices of the domestic industry by 30-40%.
- e. It is apprehended that the selling price of the domestic industry is higher than the non-injurious price and due to this, the applicants have not submitted non-injurious price in the application. In case, non-injurious price is higher than net selling price, the investigation should be terminated as per consistent practice of the Authority.
- f. The applicants have not provided any concrete evidence of likelihood of recurrence or continuation of injury.
- g. The import price from Vietnam has increased and is much higher than import price from other countries which indicates that exporters are selling at fair prices even in the absence of customs duty.

G2. Submissions by the domestic industry

53. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury, causal link and likelihood of subsidization and injury:

- a. There is no requirement of cumulative assessment of injury in the present investigation as imports from China are negligible and not causing injury to the domestic industry. Imports from Vietnam and especially due to producers not subject to anti subsidy duty have caused injury to the domestic industry.
- b. The Governments of the subject countries have continued providing subsidies to the producers of the subject goods in the subject countries.
- c. The imports from Vietnam have increased in absolute terms. The increase is from importers not subject to anti-subsidy duty.
- d. Imports from exempted producers in Vietnam have increased much more than the increase in demand.
- e. Imports from producers subject to anti-subsidy duty have declined which demonstrates the inability of the foreign producers to sell at fair prices in India.
- f. The market share of imports from exempted producers in Vietnam has increased. Such imports have taken away the potential and existing market share of the domestic industry.
- g. The market share of the Indian industry is much lower to the market share held by the Indian industry prior to the original period of investigation.
- h. The domestic industry has enough capacity to cater to the entire demand in India. Hence, reliance on imports is totally unnecessary.
- i. The imports from Vietnam are undercutting the prices of the domestic industry on average basis. The price undercutting on PCN wise basis is higher.
- j. The capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period and was the lowest during the period of investigation.
- k. The landed price of imports from Vietnam was below the cost of sales of the domestic industry.
- l. The domestic industry has been forced to compromise on margins due to low-priced imports from Vietnam. The profitability and return on investment of the domestic industry have declined.
- m. The imports are likely to increase in the absence of anti-subsidy duty. The raw material is being transferred from China to Vietnam especially after imposition of anti-subsidy duty and anti-dumping duty in India on imports of raw material from China.
- n. The Authority, in Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products held that there are significant subsidies being provided to the raw material manufacturers in China. The benefits of such subsidies have been passed through to producers in Vietnam.
- o. There are significant and excess capacities of stainless steel in China, as held by the Authority in the final findings on imports of Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products from China.

Since the subject goods are downstream products of stainless steel with minimal value addition, such exportable capacities are likely to be used for exports to India, in the absence of anti-subsidy duty.

- p. Sohna SSP and Steel 568 have reported increase in production quantity and capacity utilization. Sohna SSP has also reported increase in capacities.
- q. While producers in China PR have excess capacities, there has been decline in demand of steel in China. The Chinese producers are in need for alternate markets to absorb the excess volumes.
- r. A number of countries such as Türkiye, Eurasian Economic Union, USA and Brazil have imposed trade remedial measures on imports of subject goods.
- s. Imports are likely to depress the prices of the domestic industry and cause material injury to the domestic industry in the absence of the anti-subsidy duty.

### **G3. Examination by the authority**

- 54. The Authority has examined the arguments and counter arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 55. Rule 13 of the Countervailing Duty Rules, 1995 read with *Annexure I* provides that an injury determination involves examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of subsidised imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.
- 56. The Authority has considered submissions made by various interested parties and relevant legal provisions. The examination hereinbelow *ipso facto* deals with the submissions made by the domestic industry and interested parties concerning injury to the domestic industry.
- 57. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject countries before proceeding to examine the likelihood aspects of subsidy and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the subsidised imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure-I of the Rules.
- 58. Para 4 of Annexure I of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-subsidy investigation, the Authority may cumulatively assess the effect of such imports in case it determines that:
  - a. The margin of subsidization established in relation to the imports from each country is more than one percent and the volume of imports from each country is not negligible, and
  - b. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
- 59. With regard to the submissions by the domestic industry that there is no need for cumulative analysis, the Authority notes that the imports from China have declined and are negligible. Further, the domestic industry has stated that such imports are not causing any injury to the domestic industry. Thus, the Authority assessed the injury due to imports from Vietnam.

#### **G.3.1 assessment of demand / apparent consumption**

- 60. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	117	124
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	107	91
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Trend	Index	100	80	111	110
Imports from China	MT	36,584	408	616	129
Trend	Index	100	1	2	0
Other imports	MT	31,387	26,532	15,637	14,408
Trend	Index	100	85	50	46
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	91	96	90

61. It is seen that the demand for the subject goods declined in 2020-21 as compared to 2019-20 but increased thereafter in 2021-22 and has again declined in the period of investigation. However, the demand has largely remained stable throughout the investigation period.

### G.3.2. Volume effect of the subsidized imports

62. With regard to the volume of the subsidized imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG systems. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the subsidized imports during the injury period and the period of investigation are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Imports from China	MT	36,584	408	616	129
Other imports	MT	31,387	26,532	15,637	14,408
Total	MT	1,09,983	60,414	62,880	60,847
Imports from Vietnam in relation to					
Domestic production	%	10-20	10-20	10-20	10-20
Consumption	%	10-20	0-10	10-20	10-20

63. It is seen that:

- a. The volume of imports from Vietnam declined in the year 2020-2021 as compared to the base year of the injury investigation period. However, there has been significant increase in import volume post 2020-2021.
- b. The imports from Vietnam in relation to domestic production has increased from \*\*\*% to \*\*\*%.
- c. The imports from Vietnam in relation to domestic consumption has increased from -\*\*\*% to \*\*\*%.

### G.3.3. Price effect of the subsidized imports

64. With regard to the effect of the subsidized imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

**a. Price undercutting**

65. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

SN	Particulars	UOM	200 series	300 series
1	Landed Price of imports from Vietnam	₹/MT	1,51,493	2,50,993
2	Net selling price	₹/MT	***	***
3	Price undercutting	₹/MT	(***)	***
4	Price undercutting	%	(***)	***
5	Price undercutting	Range	(0-10)	0-10

66. It is seen that though there has been negative price undercutting in case of 200 series, however, there is a positive price undercutting in the case of 300 series ranging from \*\*\*%.

**b. Price suppression/depression**

67. In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	130	137
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	138	141
Landed price from Vietnam	₹/MT	1,56,842	1,71,120	2,02,932	2,43,168
Trend	Indexed	100	109	129	155
Landed price from China	₹/MT	1,08,347	1,33,597	2,39,300	1,83,228
Trend	Indexed	100	123	221	169

68. The Authority notes that, during the base year, the domestic industry experienced some price pressure from imports, as evidenced by the selling price falling below the cost of sales. However, post the base year of the injury investigation period, the domestic industry has been able to sell the subject goods at prices above the cost of sales, indicating an absence of price pressure—be it suppression or depression—resulting from imports on domestic prices.

69. However, based on PCN wise comparison, the Authority notes that the landed price of Vietnam for 300 series is below the selling price of the domestic industry. The domestic industry has submitted that it has been forced to compromise on margins due to the low-priced imports from Vietnam.

Particulars	Unit	200 S	300 S
Domestic Industry Selling price (Sampled)	₹/MT	***	***
Range	₹/MT	1,50,000-2,00,000	2,50,000-3,00,000
Landed price from Vietnam	₹/MT	1,51,493	2,50,993
Landed price from China	₹/MT	1,01,052	2,32,182

70. Some of the interested parties have contended that the injury to the domestic industry is due to imports from China as the landed price of imports from China is lower than that from Vietnam. The Authority notes that while the landed price of imports from China is lower than landed price from Vietnam, the volume of imports from China is negligible. Such miniscule volume cannot be considered to be a cause of injury to the domestic industry.

**G.3.4. Economic parameters of the domestic industry**

71. The Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent injury of the subject imports on the domestic producers. With regard to the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

**a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

72. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	109	131
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	119	130
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Range	%	50-60	60-70	60-70	50-60
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	117	124

73. The Authority observes that, despite the increases in capacity, production, and sales of the domestic industry over the injury period, the industry has not been able to operate at its optimum level or fully utilize its capacity.

**b. Market share**

74. Market share of the subsidized imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Domestic industry	%	20-30	30-40	30-40	30-40
Other Indian producers	%	40-50	40-50	40-50	40-50
Imports from Vietnam	%	10-20	0-10	10-20	10-20
Imports from China PR	%	0-10	0-10	0-10	0-10
Other imports	%	0-10	0-10	0-10	0-10

75. The Authority notes that the imposition of anti-subsidy duties has provided significant relief to the domestic industry, enabling it to increase its market share from \*\*\*% in the base year of the injury investigation period to \*\*\*% in the period of investigation. However, it is also observed that the trend of imports from Vietnam has experienced an upward trajectory, rising from \*\*\*% in the base year to \*\*\*% during the period of investigation.

76. Further, the applicants have submitted that the market share held by the Indian industry during the period of investigation is much lower than the market share held by the Indian industry prior to the original period of investigation. The Authority notes that the lowest market share held by the Indian industry during the injury period of the original investigation was \*\*\*% while the highest market share held by the Indian industry during the current period of investigation was \*\*\*%. Thus, the Indian industry holds market share less than it held previously.

**c. Inventories**

77. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	130	141	166

78. It is noted that the inventories of the domestic industry have increased over the injury period.

**d. Profitability, cash profits and return on capital employed**

79. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	130	137
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	138	141
Profit / (loss)	₹/MT	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	686	2,267	976
Profit / (loss)	₹ Lacs	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	761	2,652	1,234
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	448	1,129	609
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	0-10	10-20	20-30	10-20

80. The Authority notes that:

- The profitability of the domestic industry did increase till 2021-2022, however, it has declined by \*\*\*% in the period of investigation as compared to the previous year.
- The return on capital employed also showed the same trend as it increased till the year 2021-2022 but thereafter has declined in the period of investigation by \*\*\*% as compared to the previous year.
- The domestic industry has stated that it has been forced to compromise on margins due to imports from Vietnam at prices below the cost of sales of the domestic industry.

**e. Employment, wages and productivity**

81. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	105	116	137
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	119	130
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	103	95

82. It is noted that the number of employees increased over the injury period. The productivity per day has also increased over the injury, however, the productivity per employee started declining since 2020-2021 and has experienced a further decline in the period of investigation.

**f. Growth**

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	%	-	***	***	***
Production	%	-	***	***	***
Domestic sales	%	-	***	***	***
Profit/(loss) per unit	%	-	(***)	***	(***)
Cash profits	%	-	***	***	(***)
Return on capital employed	%	-	***	***	(***)

83. It is noted that the capacity has demonstrated positive growth, reaching \*\*\* % in the period of investigation compared to \*\*\* % in the base year. However, the domestic industry's production has decreased from \*\*\* % in the base year to \*\*\* % in the period of investigation. The domestic industry has also faced a decline in domestic sales, which fell from \*\*\* % in the base year to \*\*\* % during the period of investigation. Furthermore, cash profits and return on capital both turned negative during the period of investigation, despite exhibiting a positive growth rate during the injury investigation period.

**g. Ability to raise capital investment**

84. The Authority notes that although the capacity of the domestic industry has increased during the injury period, the profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation and recorded a decline in return on capital employed.

**h. Magnitude of subsidy margin**

85. The subsidy margin determined by the Authority is positive and significant in the present investigation.

**H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF SUBSIDIZATION AND INJURY**

86. Since, the present investigation is a sunset review investigation, the fact that whether domestic industry is currently not suffering injury does not impact the determination of whether the duties shall be continued or not. In a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether revocation of a measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination made in an original investigation.

87. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation of subsidisation or injury in the event of cessation of the duties. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation of subsidisation or injury.

88. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation of subsidisation and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

**H1. Continued subsidization despite existence of anti-subsidy duty**

89. The authority notes that there is a continued subsidisation of the subject goods from the subject countries inspite of the duties in force. Continued subsidisation during the existence of duties indicates the likelihood of continuation of subsidies.

90. While the volume of imports from China was negligible due to anti-subsidy duty in force, the imports of 300 series from both the subject countries are below the selling price of the domestic industry.

Particulars	Unit	200 S	300 S
Domestic Industry Selling price	₹/MT	***	***
Range	₹/MT	1,50,000-2,00,000	2,50,000-3,00,000
Landed price from Vietnam	₹/MT	1,51,493	2,50,993
Landed price from China	₹/MT	1,01,052	2,32,182

91. The Authority notes that in case of cessation of anti-subsidy duty, the imports from all sources are likely to increase. Further, such imports are likely to be at prices below the cost of sales of the domestic industry and is likely to cause injury to the domestic industry.

## H2. Decline in imports from china pr and producers subject to anti-subsidy duty

92. The Authority notes that the volume of subject imports has declined over the injury period from sources subject to anti-subsidy duty.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China	MT	36,584	408	616	129
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Imports from exempted producers	MT	25,098	31,602	43,671	42,992
Imports from other producers	MT	16,915	1,872	2,955	3,318

93. The Authority notes that the imports from producers subject to anti-subsidy duty have declined. In the event of expiry of anti-subsidy duty, the imports are likely to follow the trend of imports from sources exempted from anti-subsidy duty. Thus, such imports are likely to increase in India and cause material injury to the domestic industry.

## H3. Significant idle capacities held by producers in china pr

94. The applicants have submitted that there are significant excess capacities of stainless steel in China PR. The Authority notes, that as per the evidence on record, the demand for stainless steel has declined in China PR. Since the subject goods are downstream products of stainless steel with minimal value additions, the additional capacities of the Chinese producers are likely to be used for exporting the subject goods to India.

## H4. Measures imposed by other countries

95. The applicants have claimed that the producers in the subject countries face trade remedial measures in Türkiye, Eurasian Economic Union, USA and Brazil. The Authority notes due to imposition of trade remedial measures on imports of subject goods from the subject countries, the producers are likely to shift to Indian market in case of cessation of anti-subsidy duty. Further, since there are excess capacities in China PR, the producers in China PR are likely to export the subject goods to India in large quantities in case of expiry of anti-subsidy duty.

Date	Country imposing measure	Type of measure imposed
10-07-2021	Türkiye	Anti-dumping duty on imports from Vietnam
14-03-2021	Eurasian Economic Union	Anti-dumping duty on imports from China
03-12-2019	United States of America	Anti-dumping duty on imports from China and Vietnam
06-03-2019	United States of America	Anti-subsidy duty on imports from China
13-06-2018	Brazil	Anti-dumping duty on imports from Vietnam

## H5. Imports entering india below the selling price

96. The applicants have claimed that the imports are entering the country at prices lower than the selling price of the domestic industry.



Particulars	Unit	200 S	300 S
Domestic Industry Selling price	₹/MT	***	***
	₹/MT	1,50,000-2,00,000	2,50,000-3,00,000
Landed price from Vietnam	₹/MT	1,51,493	2,50,993
Landed price from China	₹/MT	1,01,052	2,32,182

97. The Authority notes that the landed price of subject imports was below the selling price of the sampled producers during the period of investigation.

98. The domestic industry has not suffered injury due to anti-subsidy duty in force and negligible volume of imports from China and exporters subject to duty in Vietnam. In case of cessation of anti-subsidy duty and increase in volume of imports, the domestic industry will be forced to compete with the import price. Such prices are likely to cause injury to the domestic industry.

#### H6. Likely performance of the domestic industry in case of cessation of anti-subsidy duty

99. In the event of expiry of anti-subsidy duty, the domestic industry is likely to be forced to compete with imports from the subject countries. At the present imports prices, the domestic industry is likely to suffer injury in terms of financial losses, decline in cash profits and negative return on capital employed.

100. The likely analysis of domestic industry in the absence of anti-subsidy duty.

Particulars	Unit	Actual	Likely	Change
Cost of sales	₹/MT	***	***	-
Selling price	₹/MT	***	***	(***)%
Profit / loss	₹/MT	***	(***)	(***)%
Profit / loss	₹/MT	***	(***)	(***)%
Cash profits	₹/MT	***	(***)	(***)%
Return on investment	%	***	(***)	(***)%

#### H7. Revival of domestic industry only due to imposition of anti-subsidy duty.

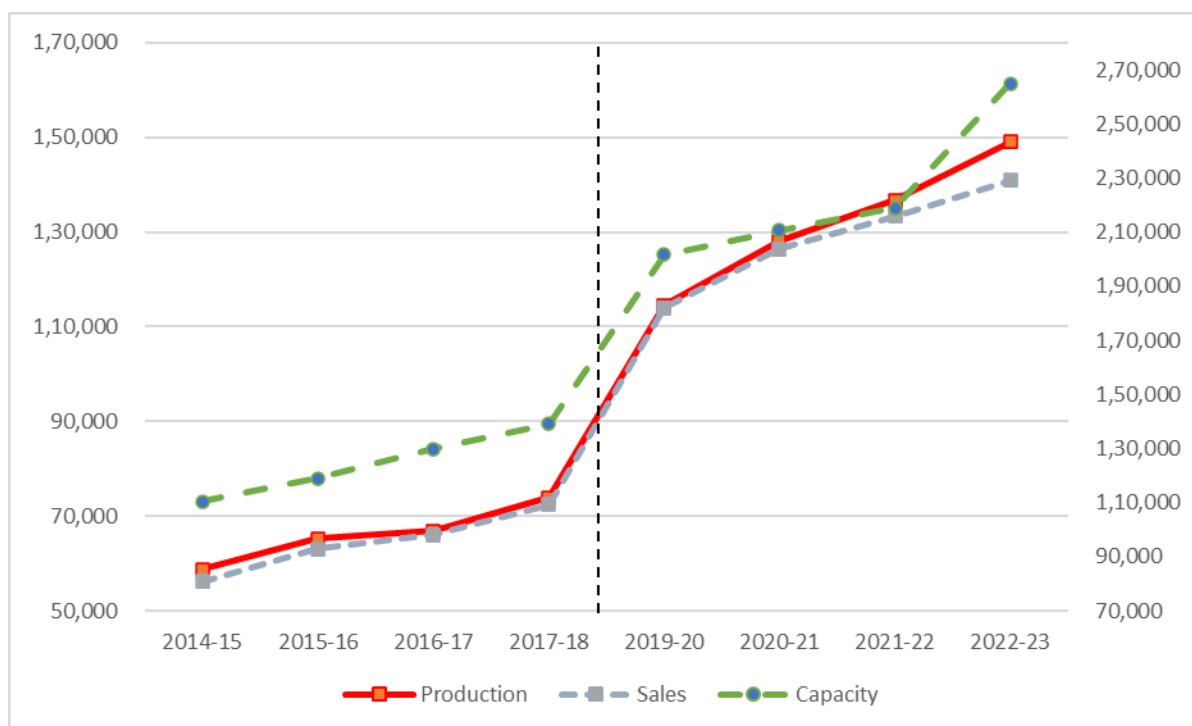
101. The Authority notes that the performance of the domestic industry has increased significantly in the current period of investigation as compared to the original period of investigation due to imposition of anti-subsidy duty. The improvement between the two periods is as a result of decline in volume of imports.

Particulars	Unit	Original POI	Current POI	Change
Volume of subject imports	MT	71,593	46,439	-35%
Imports from China	MT	43,059	129	-99.7%
Imports from Vietnam	MT	28,535	46,310	62%
Demand	MT	***	***	***
Capacity	MT	***	***	***
Production	MT	***	***	***
Capacity utilization	%	***	***	***
Domestic Sales	MT	***	***	***
Market share of imports	%	20-30%	10-20%	(50)-(60)%
Market share of Indian Industry	%	60-70%	80-90%	20-30%
Profit/Loss	₹/MT	Losses	***	

102. The capacity, production, domestic sales, market sales of the domestic industry have improved as compared to the period of investigation of the original investigation. While the domestic industry was incurring losses in the original period of investigation, it is now earning profits.

**H8. Improvement in performance due to anti-subsidy duty in force**

103. The Authority notes that the performance of the domestic industry in terms of capacity, production and domestic sales has improved drastically post imposition and during the tenure of the anti-subsidy duty.



104. Since in the absence of anti-subsidy duty in force, the subject imports are likely to enter India at low-prices and increased quantities, there is likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of anti-subsidy duty.

**H9. Imports at injurious prices**

105. The Authority notes that the subject imports have entered the Indian market at injurious prices and below the cost of sales and selling price of the domestic industry despite duties in force.

**I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

106. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.
107. As regards the contention raised by the new participating producer/exporter from Vietnam, TVL, for the grant of an individual rate of duty on the basis that this is its first opportunity to participate in the investigation, the Authority notes that TVL began exporting to India a year before the current investigation period.
108. The data provided by TVL reveals that TVL exported \*\*\* MT in the year 2021-2022 and \*\*\*MT during the period of investigation (POI), constituting \*\*\*% and \*\*\*% of the total imports into India, and \*\*\*% of the total demand in India, respectively. Furthermore, it is noted that the exports to India amount to \*\*\*% of TVL's total production during the specified periods—a figure substantially lower in both number and percentage compared to the exports made by other cooperating producers from the subject country. It is further noted that TVL's

third-country exports amounted to \*\*\*MT, representing merely \*\*\*% of its total production, \*\*\*% of its domestic sales, and \*\*\*% of the total imports to India during the POI.

109. Since the quantity exported to India by TVL is very low, this leads to a suspicion that the prices at which TVL has exported to India could be a 'manipulated' price because the current investigation is that of sunset review wherein it is possible to assess the price of the producers/exporters from the subject country. The Authority therefore needs to have a deeper scrutiny of the export price to assure itself that the export price of the limited exports from TVL truly reflects its price and has not been influenced by the prevailing anti-subsidy duties on imports from the subject country. In order to re-assure itself, the Authority has looked at TVL's exports to third countries. The purpose of this inquiry is to ascertain whether the export price of TVL to third countries was comparable to its export price to India and reach to a conclusion that the export price of TVL with such export volume is not 'coloured'. However, TVL's exports to third countries is also very low as deliberated in the earlier para.
110. In light of the aforementioned facts and circumstances, the Authority is unable to accept the export prices of TVL to India with such a low volume of exports and hence rejects TVL's claim for the grant of an individual rate of duty.
111. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
112. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Particular	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Vietnam					
a	Son Ha SSP Vietnam	***	***	***	***	Negative
b	Steel 568 Co. Ltd	***	***	***	***	0-10
g	Any other	***	***	***	***	10-20
2	China PR					
a	Any Other	***	***	***	***	30-40

#### H9. Non- attribution analysis

113. The Authority examined whether other factors listed under the CVD Rules could have caused injury to the domestic industry. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than subsidized imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidized imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

##### a. Contraction in demand

114. The demand for the subject goods declined initially but has thereafter increased over the injury period. There is no information on record to suggest a contraction in demand. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

##### b. Pattern of consumption

115. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, to which the injury suffered can be attributed.

##### c. Conditions of competition and trade restrictive practices

116. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which can cause injury to the domestic industry apart from the low-priced imports from subject countries.

**d. Developments in technology**

117. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry has suffered injury.

**e. Productivity**

118. The productivity of the domestic industry has not decreased and thus, it has not suffered injury on this account.

**f. Export performance of the domestic industry**

119. The domestic industry has segregated the export performance from the domestic performance and thus, no injury has been caused in this account.

**g. Performance of other products**

120. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the product under consideration only.

**K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES****K1. Submissions by other interested parties**

121. Other interested parties have not made any submissions with regard to the Indian industry's interest.

**K2. submissions by the domestic industry**

122. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Importers and Users have not participated or have responded to the economic interest questionnaire.
- b. The responding producers/exporters have not provided any information that may allow the Authority to determine whether the discontinuation of the duties would be in public interest. The absence of any information in this regard shows that the producers / exporters do not have any evidence or information to prove that the duties have any adverse effect on the users in India.
- c. The continuation of the duty would create favourable market conditions for the Indian steel sector as it would reduce dependence on steel imports.
- d. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry which is capable of supplying the product to the consumers in competition to fair-priced imports.
- e. The Indian industry has sufficient capacities to meet the growing demand in India.
- f. The Indian industry constitutes more than 100 of producers and imposition of duties will not create any monopoly in the Indian market.
- g. The Indian industry is fragmented and majority of the producers of like article in India are MSMEs and continuation of duties is imperative to provide them with a level playing field.
- h. The subject goods are not raw materials for other industries and thus the impact of duties, which is minimal, would not impact the performance of other industries.
- i. The subject goods are used in residential or commercial construction and the costs on account of this product forms only 0.3% of the overall cost of a construction project. The impact of proposed duty is minimal.
- j. The goods can be imported from various other countries such as Italy, Malaysia, USA and Korea RP.
- k. The duties did not have any adverse effect as the demand has increased since the original investigation.

**K3. Examination by authority**

123. The Authority notes that the purpose of duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to establish a situation of open and fair competition in the

Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-subsidy measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-subsidy duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-subsidy measures. On the contrary, continuation of anti-subsidy measures would ensure that no unfair advantages are gained due to subsidy provided, prevent decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

124. Post initiation of investigation, the Authority issued an economic interest questionnaire to all the interested parties. However, the response to the questionnaire was filed by the domestic industry and two producers from Vietnam namely Sonha SSP Vietnam and Steel 568 Co., Ltd. Apart from the said parties, no producers/exporter, importers or users of the subject goods, have participated in the investigation or filed a response to the Economic Interest Questionnaire. Further, the administrative ministry for the subject goods and the downstream product has also not objected or made any statement regarding the continuation or expiry of duty.
125. The Authority notes that no evidence has been provided to show that the duties in force have resulted in a deterioration in the performance of the users, or may lead to such deterioration. As noted above, despite the Authority providing an opportunity to provide structured and substantiated information, in the response to the economic interest questionnaire, the users have abstained from participating in the present investigation. In view of the same, the Authority notes that it cannot be concluded that the continuation of measures would result in an adverse impact on the domestic industry.
126. In this regard, the Authority also notes that the domestic industry had furnished quantified impact of anti-subsidy duty on the users. As per the information shared by the domestic industry, the impact on users was in about 0.03%.

Particulars	Unit	Rate
Cost of Land	₹ Lakhs	***
Cost of Construction of Building	₹ Lakhs	***
Total Cost of Building	₹ Lakhs	***
Cost of WSSTP	₹ Lakhs	***
Highest CVD imposed	%	29.88%
Lowest CVD imposed	%	10.33%
Cost of CVD in total building (Highest)	₹ Lakhs	***
Cost of CVD in total building (Lowest)	₹ Lakhs	***
Impact with Highest CVD	%	0-0.10%
Impact with Lowest CVD	%	0-0.10%

127. With regard to the availability of the like article in the country, the Authority notes that the anti-subsidy duty does not restrict imports from the subject countries, but only provides a level playing field. Such a level playing field shall allow many MSME companies to flourish in the Indian market. The Indian industry has sufficient capacity to cater to the growing demand in India. Since the imposition of duties, the demand has increased. This shows that the duties have reduced the dependency on imports and allowed the Indian industry to grow.
128. As per the information on record there is sufficient capacity in India to cater to domestic demand. This shows that the imposition of countervailing duties has allowed the country to add more capacity.
129. The fragmented nature and presence of multiple producers would also ensure *inter-se* competition between the domestic producers. As a result, the users would be assured of competitive prices in the domestic market, and easy availability of the subject goods. The applicants have also highlighted that the product can also be imported from other countries.
130. In view of the foregoing, the Authority concludes that continuation of duty would not have an adverse impact on the users as well as to the availability of the subject goods in the domestic market.

**L. POST DISCLOSURE COMMENTS****L1. Submissions by other interested parties**

131. TVL argues that the Customs Tariff Act, 1975 or the Countervailing Rules does not prohibit individual duty grants for low export volumes. The Authority has granted individual duty rates in past cases, such as in 2007 and 2008 for imports of DI Pipes and Ceftriaxone Sodium Sterile despite having only two export transactions to India. The respondent requests the Authority to be consistent in granting individual duty rates.
132. In addition to the above submission TVL requests the Authority that if its request for individual duty rates gets rejected, it should be allowed to approach the Authority with a New Shipper Review.

**L2. Submissions by domestic industry**

133. The NIP computed by the investigation team appears to be unduly low. The domestic industry under investigation is classified as MSME, therefore the producer's records may not match the standards of the organized sector in terms of quality and quantity. Therefore, their cost should not be normated and NIP should be calculated on their actual cost basis.

**L3. Examination by the Authority**

134. Regarding TVL's concern about the individual duties assigned to exporters with only two transactions in the POI, the Authority notes that both the cases cited by TVL, the concerned parties had a history of exporting prior to the POI, and it was during the POI that they had only two transactions of exports to India. However, TVL's export volumes were low both during the POI and the year prior to it. This circumstance does not allow the Authority to be reasonably affirm that TVL's export prices are not manipulative. As mentioned earlier, the Authority tried to have a deeper scrutiny of the export price to assure itself that the export price of the limited exports from TVL truly reflects its price and has not been influenced by the prevailing anti-subsidy duties on imports from the subject country. In order to re-assure itself, the Authority has looked at TVL's exports to third countries. The purpose of this inquiry was to ascertain whether the export price of TVL to third countries was comparable to its export price to India and reach to a conclusion that the export price of TVL with such export volume was not 'coloured'. However, TVL's exports to third countries was also very low and hence the Authority rejected TVL's claim for the grant of an individual rate of duty.
135. Furthermore, in an original investigation, interested parties do not have access to data or information that would enable them to manipulate or influence export prices to their advantage. However, in a sunset review investigation, the duties imposed by the Authority in the original investigation are in public domain. This information could potentially enable new exporters to manipulate their prices. The circumstances of the investigations cited by TVL pertains to original investigations and that cannot be compared with the current investigation which is a sunset review. Had it been the original investigation, the low export volumes may not have needed such a deeper scrutiny to analyse the true reflection of prices but since this case is that of a sunset review where the impact of anti-subsidy duties on prices are already known to the stakeholders, therefore to say that the low export volumes should be considered and the exporter/producer should be granted an individual rate of duty under the straight jacket formula cannot be appreciated.
136. With respect to the contention raised by the domestic industry on non injurious price (NIP), the Authority notes that the non-injurious price of the product under consideration is calculated in accordance with the provisions of Annexure III of the Anti-dumping (AD) Rules 1995 which provides that the best utilization of raw materials, utilities and capacity utilisation by the constituents of the domestic industry, over the past three years period and the POI and at the POI rates may be considered to nullify injury if any, caused to the domestic industry by inefficient utilisation of raw materials, utilities and capacity utilisation. Further, the Authority notes that there is no provision in AD rules 1995 to exempt the methodology of determination of NIP for MSMEs sector.

**M. CONCLUSION**

137. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis

of the likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- i. The product under consideration in the present investigation is Welded Stainless Steel Tubes and Pipes classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff codes 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The domestic industry has submitted that the subject goods are also being imported under the HS Codes 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation.
- ii. The Authority notes that the only Chinese producer which participated in the original investigation did not participate in the current review investigation. Similarly, few producers from Vietnam who participated in the original investigation also did not participate in the current investigation. Therefore, they are considered as non-cooperative in the present sunset review investigation. Analysis of import data however shows exports having been made by these exporters attracting specific duty. The Authority therefore in the absence of any cooperation from such participating producers/exporters in the original investigation proceeds to shift their duties from individual to residual category.
- iii. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China and Vietnam.
- iv. The applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
- v. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review and the application contained sufficient *prima facie* evidence to justify initiation of the present sunset review. Further, the applicants provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation.
- vi. However, there is a likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present countervailing duty, as established by the following factors:
  - a) There is a decline in demand of the subject goods however the decline in imports has not been in accordance with the decrease in demand. Further, imports from Vietnam increased in relation to domestic production and consumption.
  - b) The volume of imports in India have declined from China. This decline in volume of imports is due to the anti-subsidy duty in force. Such limited imports were undercutting the prices of the domestic industry and were priced below the cost of sales of the domestic industry. The domestic industry has not suffered any injury due to such imports as the volume was insignificant but in the event of cessation of the current duties, these low priced imports have a high chance to flood the domestic market with huge quantities injuring the domestic industry.
  - c) The volume of imports from Vietnam increased substantially in POI as compared to 2020-21. The landed price of Vietnam for 300 series is below the selling price of the domestic industry. The domestic industry is forced to compromise on margins due to the low-priced imports from Vietnam.
  - d) Production, capacity, sales volume and market share in demand of the domestic industry showed positive growth over the injury period due to anti subsidy duty in place. However, capacity utilisation, return on investment, cash profit and PBIT decreased in POI demonstrating need for continuation of countervailing duty.
  - e) In case of cessation of anti-subsidy duty, the domestic industry is likely to incur financial losses.
  - f) Chinese producers have excess capacities for the product under consideration. The demand for stainless steel has declined in China PR. The additional capacities of the Chinese producers are likely to be used for exporting the subject goods to India once the duties ceased to exist.

- g) Producers in the subject countries are facing trade remedial measures in Türkiye, Eurasian Economic Union, USA and Brazil and have lost export volumes to these countries. Therefore, these producers are likely to shift their exports to Indian market in case of cessation of anti-subsidy duty.
- h) Imports are entering at prices below the selling price of the domestic industry. In case of cessation of anti-subsidy duty, the import price is likely to be lower and there is all the probability that in absence of the current duties, the export volumes will rise with such low priced imports creating a likelihood of injury to the domestic industry.

#### N. RECOMMENDATIONS

138. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties including Government of China PR and Government of Vietnam and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of subsidies, injury, causal link, likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of sunset review investigation as laid down under the Countervailing Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty imposed on subject goods is required to be extended further, the Authority recommends extension of countervailing duties on imports of the product under consideration.

139. Accordingly, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-subsidy duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR and Vietnam as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

#### DUTY TABLE

S.No.	Heading/sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as a % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73064000, 73066100, 73066900, 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90#	Welded stainless steel pipes and tubes	Any country other than China PR	China PR	Any Producer	29.88
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any Producer	29.88
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited	NIL
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Steel 568 Co., Ltd	NIL



5	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.	11.96
6	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than 2 to 4 above	11.96
7	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any producer	11.96

*#The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

140. An appeal against the order of the Designated Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority